

आज सीएम यादव पन्ना में 204 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 22 विकास कार्यों की देंगे सौगात

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पन्ना प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय स्थित होमगार्ड ग्राउण्ड पन्ना में आयोजित कार्यक्रम में 204 करोड़ 26 लाख रूपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें 94 करोड़ 63 लाख रूपये के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109 करोड़ 63 लाख रूपये के 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शासकीय सांदीपनि उ.मा. विद्यालय गुनौर एवं पर्वई तथा शासकीय महाविद्यालय पर्वई के नवीन भवन निर्माण का लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त बृजपुर एवं सुहवा बैराज योजना सहित बृहस्पति कुंड के सौंदर्यीकरण एवं प्लास फ्लोर व व्यू प्वाइंट सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव चार मार्गों क्रमशः टाई पहुंच मार्ग, मकरंदगंज-हरद्वारी-गुनौर, मड़वा से बंधा एवं

सतैया-झरकुआं-पगरा-बम्हौरी मार्ग के सुदृढीकरण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। डायमंड म्यूजियम, संयुक्त एसडीएम कार्यालय भवन पन्ना सहित छत्रसाल पीजी कॉलेज पन्ना के विज्ञान भवन रेनोवेशन, उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। गीता पेट्रोल पम्प से पोस्ट ऑफिस तिराहा तक रोड, डिवाईडर निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों और स्वच्छ भारत मिशन शहरी अंतर्गत जल प्रबंधन कार्य का भी भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पर्वई के 370 वर्गमीटर निर्माण कार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में कर्मशाला एवं नवीन भवन निर्माण, शासकीय उ.मा. विद्यालय उत्कृष्ट पर्वई में 100-100 सीटर बालक व बालिका छात्रावास निर्माण, शासकीय हाईस्कूल रक्सेहा एवं भापतपुर कुर्मियान के हायर सेकेण्डरी में उन्नयन निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया जायेगा।

आनंद परिस्थितियाँ नहीं, मन की अवस्था से तय होता है

एमसीयू में फैकल्टी ने सीखे प्रसन्न और सहज़ शिक्षक बनने के गुर

भोपाल। एक शिक्षक कैसे हैसमुख, शांतचित्त और ऊर्जावान हो सकता है, इस विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला बुधवार को प्रारंभ हुई। प्रथम दिन तीन सत्रों में व्यक्तित्व में सकारात्मकता लाने के उपायों पर विशद चर्चा हुई।

मुख्य अतिथि हैदराबाद के रेखी फ़ाउंडेशन के प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रैक्टिस डॉ श्रीहरि कृष्ण ने कहा कि खुशी या आनंद को अभ्यास से पैदा किया जा सकता है। आखिर एक सा बाहरी वातावरण होने के बावजूद एक व्यक्ति सुखी और एक दुखी क्यों होता है। खुशी को परिस्थितियाँ नहीं, मन की अवस्था तय करती है। संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के रेखी सेंटर आफ़ एक्सपीलेंस फ़ॉर साइंस आफ़ हैप्पीनेस ने किया है। इसमें विवि के शिक्षकों के साथ ही अतिथि शिक्षक भी भाग ले रहे हैं। श्री हरि के अलावा फ़ाउंडेशन की सीनियर फ़ैकल्टी डॉ ऋतु शर्मा तीन दिन तक प्रसन्न और सकारात्मक शिक्षक बनने के टिप्स बताएंगे।

पहले दिन दोनों विशेषज्ञ ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मन की खुशी को तय करने, उसका अनुभव करने और उससे होने वाले लाभों को सबके समक्ष रखा।

संवाद के जरिये शिक्षकों ने अनुभव साझा किए जिसमें उन्होंने उन किस्सों को बताया जब उन्हें विद्यार्थियों के बीच बहुत सुखद अनुभूति हुई या विद्यार्थी ने उनमें रुचि ली। वक्ताओं ने ध्यान देने (अटेंशन) और विषय पर ध्यान केन्द्रित करने

हम सोचे कि सकारात्मक कर सकते हैं : कुलगुरु

कार्यक्रम का शुभारंभ लता मंगेशकर सभागृह में कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने रोजगार की आपाधापी में हैं लेकिन इसमें एक खिड़की ऐसी खुली रखनी चाहिए जो आनंद का बाव दे सके। उन्होंने ओशो कम्प्यून की कार्यप्रणाली का अनुभव बताते हुए कहा कि वहाँ व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कामों को अपने अनुसार नियोजित कर ज्यादा सक्रिय व ऊर्जावान बना रहता था और रचनात्मकता का प्रदर्शन करता था। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या सकारात्मक कर सकते हैं। श्री तिवारी ने शिक्षकों से कहा कि वे नियमित पाठ्यक्रमों से अलग व्यावहारिक जीवन में विद्यार्थियों को कुछ विशिष्ट करने को प्रोत्साहित करें तो उत्कृष्ट प्रतिभाएँ निकलेंगी।

(फोकस) के गुर बताए।उन्होंने कहा कि फ़ोकस एक करेसी है और प्रायवेसी आज की लक्ज़री।

सोशल मीडिया के ज़रिए पैदा किए जा रहे डिस्ट्रेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि हमें तय करना होगा कि अटेंशन कहाँ और कब करना है। हम सूचनाओं का उपभोग तो ख़ूब कर रहे हैं किन्तु खुद की सुचनात्मकता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी ऊर्जा को अटेंशन के साथ एक दिशा में प्रवाहित करने से ही सफलता मिलती है।

राहुल ने विपक्ष के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला

- राष्ट्रगान गाया, मोबाइल की टॉच जलाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेपरलीक और

मार्च के पहले राहुल के घर पर विपक्षी

सांसदों ने बैठक की। पुलिस ने मार्च के



छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने

विपक्ष के नेताओं के साथ गुरुवार शाम को उनके घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकाला।

उनके साथ शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), टीएमसी, जेएमएम,आरजेडी लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आईयूएमएल के नेता भी शामिल रहे। इस मौके पर राहुल ने कहा-पेपरलीक के चलते जिन छात्रों को खो दिया है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे छात्र सड़कों पर हैं, इसलिए विपक्ष के सभी सांसदों को लगा कि हमें भी सड़कों पर उतरना चाहिए।

सपा सांसद अफजल भीफंसे मुख्तार के गिरोहकी थी साजिश

गाजीपुर में 5 1 लाइसेंस पर 145 हथियार!



तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि यह गड़बड़ी सांसद अंसारी ने

दोनों क्लकों की मिलीभगत से की थी। अब पुलिस मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गिरोह के गुप्तों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भोपाल में मकान का हिस्सा गिरा, एक घायल, रतलाम रेलवे मंडल की 7 ट्रेन लेट

उमरिया में जोहिला डैम का एक गेट खुला

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे से रुक-रुककर कहीं धीमी, कहीं तेज बारिश जारी है। ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूबी हैं। गुरुवार को उमरिया जिले में जोहिला डैम का एक गेट आधा मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।

भोपाल में 90 साल पुराने जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से एक युवक घायल हो गया। इंदौर में गंगवाल चौराहे से राजमोहल्ल के लिए निकली बारात में शामिल बाराती तेज बारिश के कारण रास्ते में ही रुक गए। दूल्हा डीजे के साथ अकेले ही आगे बढ़ता नजर आया।

वहीं, मुंबई में भारी बारिश की वजह से रतलाम मंडल से गुजरने वाली 7 रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं।

मौसम विभाग ने इंदौर-उज्जैन समेत 17 जिलों में 24 घंटे के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ऊपर मानसून ट्रफ, ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ईस्ट-वेस्ट शियर जोन सक्रिय हैं। इनकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है, जिससे कई इलाकों में कम समय में तेज बारिश हो रही है।



मुंबई में भारी बारिश, 4 ट्रेनें रद्द, 2 का रूट बदला ; रतलाम मंडल से गुजरने वाली 7 ट्रेनें लेट

मुंबई रेल मंडल के भिलाड और बोरीवली सेक्शन में लगातार भारी बारिश से जलभराव हो गया है। इसके चलते पश्चिम रेलवे ने रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 2 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि 7 ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं।

साल भर पहले मिली बिजली

200 खंभों से तार चोरी होने से फिर छाया अंधेरा, सांपों के खौफ में लालटेन से कट रहीं रातें

शहडोल (नप्र)। मध्य

प्रदेश के शहडोल जिले का कोटि गांव पिछले एक महीने से मानो मध्यकाल के दौर में लौट गया है। चोर गांव के करीब 200 खंभों से बिजली के तार चुरा ले गए, जिसके बाद से पूरे गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के इस मौसम में जहरीले सांपों और बिच्छुओं के डर से ग्रामीण रात-रात भर लालटेन और दिबरी जलाकर रखवाली करने को मजबूर हैं।

बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कोटि गांव के बेबस ग्रामीण अपनी समस्या लेकर 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे।



जंगल से सटे इलाके में सुरक्षा का बड़ा संकट

जंगलों से घिरे होने के कारण इस गांव में बारिश के दिनों में जहरीले जीवों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साल भर पहले ही गांव में रोशनी पहुंची थी, लेकिन चोरों की करतूत और प्रशासनिक खिलाई ने ग्रामीणों को फिर से दीये और लालटेन के दौर में धकेल दिया है। ग्रामीणों को अब जल्द से जल्द नए तार बिछाकर बिजली सप्लाई बहाल होने का इंतजार है।

ठप हुई पढ़ाई और खेती, मोबाइल चार्ज होना भी बंद

शहडोल जिले की जैतपुर विधानसभा के बुढ़ार जनपद अंतर्गत आने वाले कोटि गांव में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। एक महीने से जारी ब्लैकआउट के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। किसान सिंचाई पंप नहीं चला पा रहे हैं, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई है और मोबाइल चार्ज न होने से गांव का संपर्क बाहर से कट गया है। सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि रात में किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना बेहद ज़ोखिम भरा हो गया है।

घाटी में लश्कर के 2 आतंकियों के घर पर चल गया बुलडोजर

- जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल की हत्या में थे शामिल

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रशासन ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के घर आईईडी लगाकर ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई लाल चौक में पुलिस बल के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के एक दिन बाद की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जिन आतंकियों के मकान गिराए गए उनमें बिजबेहड़ा के गुरी गांव निवासी आदिल ठेकर और हसनपोरा निवासी हारून गनई शामिल हैं। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कॉन्स्टेबल कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में ये दोनों आतंकी भी शामिल थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग स्थित लाल चौक पर आतंकियों ने इस कारयाना वारदात को अंजाम दिया था।



अंसारी के लाइसेंस की पत्रावली गायब-पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभिलेखागार में पत्रावलियां मौजूद नहीं हैं। अफजल अंसारी के नाम से जारी लाइसेंस संख्या 1188 पी2 की पत्रावली भी गायब मिली। यह गड़बड़ी कलेक्ट्रेट के शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत से की गई थी। लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल (नंबर 830405) की जानकारी भी नहीं मिली। इस पर पुलिस ने लाइसेंसधारक अफजल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक 30 साल पहले भी अलग-अलग जांच एजेंसियों ने इस मामले में कार्रवाई की थी। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से फर्जी लाइसेंस जारी किए गए थे।

बांग्लादेश जैसा न हो जाए भारत का हाल

- जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर तसलीमा नसरीन की चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)।जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर जुटे कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें बांग्लादेश के जुलाई 2024 के



छात्र आंदोलन की याद आ गई। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण और मरिेट के मुद्दे से हुई थी, लेकिन बाद में वह सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गया। तसलीमा नसरीन ने दावा किया कि बांग्लादेश आज भी उस आंदोलन के बाद की स्थिति की कीमत चुका रहा है। उनके मुताबिक, वहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई और देश में हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आतंकवाद और अराजकता बढ़ी। यह उनकी व्यक्तिगत राय है, जिसे उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में साझा किया। तसलीमा नसरीन ने लिखा कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें जुलाई 2024 के बांग्लादेश आंदोलन की याद आ गई। उन्होंने दोनों घटनाओं के बीच अपनी आशंका का जिक्र किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के संचालन समीक्षा की

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने श्योपुर एवं सिंगरौली शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की शैक्षणिक एवं चिकित्सीय व्यवस्थाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों महाविद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर संचालन को उच्च गुणवत्ता एवं दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में फैकल्टी की उपलब्धता, तृतीय श्रेणी (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती, चिकित्सा उपकरणों एवं फर्नीचर की उपलब्धता, आवश्यक प्रोक्टोरिमेंट कार्यों की प्रगति, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं और आउटसोर्स मानव संसाधन की व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि फैकल्टी सहित सभी आवश्यक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन भुगतान एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि श्योपुर एवं सिंगरौली जैसे आकांक्षी क्षेत्रों में स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने दोनों महाविद्यालयों के निर्माण एवं विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और विद्यार्थियों एवं मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराज एस, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार, अपर संचालक स्वास्थ्य श्री मनोज कुमार सरयाम, प्रभारी अधिष्ठाता (डीन) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल से मिले मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल

मंत्रालय में नीति आयोग के सीईओ बने अनुराग जैन की विदाई

भोपाल (नप्र)। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाए गए अनुराग जैन से आज दिन भर मंत्रालय में अफसरों की मेल मुलाकात चलती रही।

इधर राज्य शासन द्वारा नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए अशोक बर्णवाल ने आज चार्ज संभाल लिया है और इसके बाद वे राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात करने लोकभवन भी पहुंचे हैं।

नए सीएस बर्णवाल सीएम डॉ. मोहन यादव से कल ही मुलाकात कर चुके हैं। मुख्य सचिव ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से भी मुलाकात की।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज नीति आयोग के सीईओ के पद से विदाई के पहले मंत्रालय पहुंचने वालों से मुलाकात कर सभी की बधाइयां स्वीकार की।इस दौरान उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि नए पद की



जिम्मेदारी संभालने के पहले वे कुछ दिन अवकाश पर रहेंगे क्योंकि जब नए पद की जिम्मेदारी संभालेंगे तो फिर छुट्टी मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के

दौरान मिले सहयोग के लिए बधाई देने पहुंचने वाले अफसरों को धन्यवाद भी किया।

दूसरी ओर नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने भी आज नई जिम्मेदारी संभाल ली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

प्रगति, चुनौतियां और आगे की राह पर हुआ राष्ट्रीय सेमिनार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग और मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: प्रगति, चुनौतियां और आगे की राह विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 21-22 जुलाई 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सेमिनार में नीति-निर्माता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, विकास भागीदार, संयुक्त राष्ट्र को एजेंसियां और देश भर से राज्य खाद्य आयोगों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीतिगत संवाद और आपसी सीख के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करना था।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत खाद्य, नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को सामाजिक न्याय का आधार बताया, जो कमजोर नगरिकों के लिए सम्मान और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करता है। लगभग 28,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा दी जा रही है। श्री राजपूत ने नवाचारों की प्रमुख पहलों पर

भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में राशन आपके द्वार (डोरस्टेप डिलीवरी) योजना, लाभार्थियों को रसू-आधारित अलर्ट, दिव्यांगजनों के लिए प्रॉक्सी राशन संग्रह और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना कर रहे बुजुर्ग नगरिकों के लिए विशेष सहायता योजना के बारे में बताया। भारत के भविष्य के खाद्य ढांचे की रूपरेखा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. वी.के. मल्होत्रा ने प्रस्तुत की और इसके बाद विशिष्ट अतिथि प्रो. रमेश चंद्र (विशिष्ट प्रोफेसर, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस - आईसीआरआईआर,और नीति आयोग के पूर्व सदस्य) ने अपने विचार रखे। इसके बाद हुए तकनीकी सत्रों में संरचनात्मक चुनौतियों, वित्तीय स्थिरता और प्राौद्योगिकी-संचालित आपूर्ति श्रृंखला सुधारों की समीक्षा की गई, जिसमें नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योशिया सूरि ने महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सूत्री नोजोमी हाशिमोटो; आईएमएमआर-नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डॉ. सी. साई राम; और फूड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद और नेशनल लॉ स्कूल के प्रतिनिधि शामिल थे।

भोपाल(नप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केन्द्र ने नीति आयोग का सीईओ बनाया है। 1989 बैच के अनुराग जैन की छवि ब्यूरोक्रेस में एक सख्त अधिकारी की है। मीटिंग में वह खरी-खरी बातें करते हैं। एमपी आने से पहले वह पीएम मोदी की टीम के हिस्सा भी रहे हैं। काम टाइमलाइन पर पूरा हो यह उनकी पहचान है। यही वजह है कि दिल्ली उन पर भरोसा करती है।

लगभग दो साल रहे एमपी के मुख्य सचिव- 1989 बैच के आईएस अधिकारी अनुराग जैन तीन अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। 2025 में वह रिटायर होने वाले थे। लेकिन केन्द्र की मंजूरी के बाद उन्हें सीधे एक साल एक्सटेंशन मिल गया था। सितंबर 2026 तक उनका कार्यकाल बचा हुआ था। इससे पहले उन्हें नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया। आदेश जारी होने पर वह सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंचे।

एमपी में बेदाम रहा करियर- अनुराग जैन को छवि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अलग है। वह बेहद सादगी के साथ वह रहते हैं। वहीं, मीटिंग के दौरान हमेशा अधिकारियों के साथ उन्होंने खरी-खरी बातें की है। उनके कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की। साथ ही हर टास्क को बखूबी पूरा किया है।

पहली मीटिंग में ही इरादे स्पष्ट कर दिए- अक्टूबर 2024 में जब वह दिल्ली से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनकर आए तो पहली मीटिंग में ही अधिकारियों के सामने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी थी कि हम आइएसएस हैं, हमें सब कुछ आता है। इस भावना से काम न करें। सभी के

खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम, मेडिकल सुविधाएं, दर्शक दीर्घा, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, आईटी नेटवर्क तथा अन्य सभी आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक व्यवस्था का पूर्व परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने परिसर में प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सड़क संपर्क, हरित क्षेत्र, फायर सेफ्टी, साइनेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था तथा प्रशासनिक भवनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सार्वजनिक सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए तथा गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक

‘मैं चीफ कम्प्लेंट ऑफिसर बन गया हूं’

बेहद सख्त हैं नीति आयोग के नए सीईओ अनुराग जैन, पीएम मोदी के साथ भी किया है काम



साथ समनव्य स्थापित करेंगे चर्चें।

मैं चीफ कम्प्लेंट ऑफिसर बन गया हूं- मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के अंदर खटपट की खबरें भी आती थीं। अप्रैल 2026 में अधिकारियों की मीटिंग में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा था कि इस समय मैं चीफ कम्पलेंट ऑफिसर बन गया हूं, हर तरह की विवाद और समस्याएं मेरे पास ही पहुंच रही हैं।

कौन हैं अनुराग जैन- दरअसल, 11 अगस्त 1965 को जन्मे अनुराग जैन ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है। वह कॉलेज के सेकंड टॉपर रहे हैं। यूपएस के मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से 2005 में लोक प्रशासन में एमए किया था।

पीएमओ में कर चुके हैं काम- नीति आयोग के नए सीईओ अनुराग जैन प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। वह 2015 में पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात रहे

हैं। उनके पास पीएमओ में विभिन्न मंत्रालयों के बीच समनव्य की जिम्मेदारी थी। इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा करते हैं।

हाईवे मैन की उपाधि- अनुराग जैन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव भी रहे हैं। मंत्रालय के बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने गति दी है। खासकर पीएम गति शक्ति परियोजना काफी अहम रहा है। हाईवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की वजह से ब्यूरोक्रेसी में लोग इन्हें हाईवे मैन भी कहते हैं।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में रहे हैं कलेक्टर- अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश में भी काफी काम किया है। वह प्रदेश के मंदसौर, मंडला और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया है। ऐसे में उनकी छवि हमेशा निर्विवाद रही है। अब दो साल तक अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ रहेंगे।

महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में मंत्री सारंग

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को नाथुबरखेड़ा स्थित निर्माणधीन अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों एवं प्रस्तावित महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ परिसर का विस्तृत भ्रमण कर खेल अधोसंरचना, सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेस-1 का लोकार्पण शीघ्र किया जाएगा। फेस-1 के प्रारंभ होने के साथ ही यहां एथलेटिक्स, हॉकी एवं फुटबॉल की खेल गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। इन खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए मैदान एवं अत्याधुनिक

सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश में ऐसी खेल अधोसंरचना विकसित करना है, जहां प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों। यह परिसर भविष्य में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और बड़े खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा तथा मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी खेल राज्यों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के आयोजन से पूर्व एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी र्फ, फुटबॉल मैदान,

खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम, मेडिकल सुविधाएं, दर्शक दीर्घा, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, आईटी नेटवर्क तथा अन्य सभी आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक व्यवस्था का पूर्व परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने परिसर में प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सड़क संपर्क, हरित क्षेत्र, फायर सेफ्टी, साइनेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था तथा प्रशासनिक भवनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सार्वजनिक सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए तथा गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक

निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप हो तथा समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित तकनीकी निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकताानुसार थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। साथ ही परिसर में सौर ऊर्जा के उपयोग, आधुनिक कैफेटेरिया, पर्याप्त पार्किंग, हरित विकास एवं अन्य जनसुविधाओं को भी प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल एक खेल परिसर नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की नई खेल पहचान का प्रतीक बनने जा रहा है। यहां विकसित हो रही विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में भी प्रदेश को अग्रणी बनाएंगी। निरीक्षण के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित तकनीकी निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकताानुसार थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। साथ ही परिसर में सौर ऊर्जा के उपयोग, आधुनिक कैफेटेरिया, पर्याप्त पार्किंग, हरित विकास एवं अन्य जनसुविधाओं को भी प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल एक खेल परिसर नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की नई खेल पहचान का प्रतीक बनने जा रहा है। यहां विकसित हो रही विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में भी प्रदेश को अग्रणी बनाएंगी। निरीक्षण के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल ■ शुक्रवार, 24 जुलाई 2026

सुबह सवेरे

3

मप्र पुलिस में विभिन्न श्रेणियों के 9 हजार 662 पदों की एक ही दिन में मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन दिवस पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य अचलब किया जाए। उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति के अभियान में सर्वाधिक लागभग 25 हजार पदों पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति पर हर्ष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए थे कि आगामी महीनों में भी रिक्त पदों की पूर्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के तारतम्य में गृह विभाग ने विभिन्न श्रेणी के 9 हजार 662 पदों की स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदोन्नति की प्रक्रिया भविष्य में भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पदोन्नति से शेष अधिकारियों, कर्मचारियों को चक्रीय क्रम में पदोन्नत करने के आदेश भी सितंबर माह में जारी करने के निर्देश दिए हैं।

अब एआई से पकड़ा जाएगा मुंह का कैंसर

गांधी मेडिकल कॉलेज ने बनाई स्क्रीनिंग तकनीक, भारत सरकार ने दिया पेटेंट

भोपाल (नप्र)। देश में तेजी से बढ़ रहे ओरल (मुख) कैंसर को चुनौती के बीच गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) भोपाल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो शुरुआती स्तर पर ही कैंसर की पहचान करने में मदद करेगी। महाविद्यालय के डेंटल सर्जरी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ओरल कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है, जिसके डिजाइन



गांवों तक पहुंचेगी स्क्रीनिंग, संदिग्ध मरीज सीधे होंगे रेफर

डेंटल सर्जरी विभाग द्वारा विकसित 'मुख आरोय' ऐप को विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्यकर्मियों के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रारंभिक जांच की जा सकेगी। यदि किसी मरीज में कैंसर के लक्षण मिलते हैं तो ऐप के जरिए उसे तत्काल विशेषज्ञ अस्पताल में रेफर किया जा सकेगा, जिससे इलाज में होने वाली देरी कम होगी।

मंत्री काश्यप ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के लिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं को सुना।



मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कार्यकर्ताओं की जनसमस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के लिए प्रेषित किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

भोपाल में छात्र-युवाओं का राज्य स्तरीय प्रदर्शन, बोले-यह पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है



भोपाल (नप्र)। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हूड पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुडवार को राधानाथी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शभर के छात्र-युवा एकजुट हुए। मूवमेंट ऑफ्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के करीब 20 जिलों से छात्र, युवा और नर्सिंग स्टूडेंट्स शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार, ठेका प्रथा और नर्सिंग छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में तख्तियां और पोस्टर नजर आए। सबसे अधिक चर्चा उस पोस्टर की रही, जिस पर लिखा था-यह पेपर लीक नहीं, सिस्टम का लीकेज है। कई छात्र सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तस्वीरें लेकर पहुंचे और उनके आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें भी साथ लाए। युवाओं ने नारे लगाए-मन की बात तो करते हैं, मगर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती?

संपादकीय

बर्णवाल पर भरोसा

वरिष्ठ आईएसएस अशोक बर्णवाल की कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद राज्य में नया सीएस कोन होगा, इन अटकलों पर विराम लग गया है। हालाँकि बर्णवाल की नियुक्ति कार्यवाहक मुख्यब सचिव के रूप में हुई है, लेकिन जिस तरह उनके नाम पर मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार की सहमति बनी है, उससे यह तय माना जा रहा है कि वर्तमान सीएस अनुराग जैन के निवृत्त होते ही बर्णवाल काम सभाल लेंगे। अनुराग जैन केन्द्र सरकार को पसंद रहे हैं और उन्हें अब प्रतिष्ठित नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। वहां उनका कार्यकाल दो साल का होगा। वैसे भी अनुराग जैन दिल्ली जाने के मूढ़ में थे। हालांकि वो रहने वाले ग्वालियर के हैं। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही अनुराग जैन स्वयं अशोक बर्णवाल को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने ले गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बर्णवाल को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। अशोक बर्णवाल 1991 चेच के मप्र कैडर के आईएसएस अधिकारी हैं। दरअसल बर्णवाल की नियुक्ति से मप्र कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारियों की सीएस बनने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इनमें पहला नाम डॉ. राजेश राजौरा का है। वो बर्णवाल से भी उम्र में वरिष्ठ हैं। उनके अलावा केंद्र में पदस्थ मनोज गोविल, पंकज अग्रवाल भी इस लिस्ट में शामिल थे। इसी तरह अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मन्तु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोटों के नाम भी चर्चा में थे। अशोक बर्णवाल अनुराग जैन के सर्वाधिक भरोसे के अधिकारी बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि अनुराग जैन की सिफारिश पर ही बर्णवाल को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अवतक बर्णवाल स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण, कृषि, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रशासन से जुड़े विभिन्न जटिल विभागों का बड़ी कुशलता के साथ संचालन करते आए हैं और इन जिम्मेदारियों पर उन्हें 35 साल का लंबा अनुभव भी है। तकनीकी और प्रबंधकीय योग्यता में भी उनकी महारत झलिल है। उन्होंने बोटक (माइनिंग इंजीनियरिंग) के साथ-साथ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी यही पृष्ठभूमि नीतिगत चुनौतियों को तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से हल करने में मददगार साबित होती है। जटिल क्षेत्रों में पीपुल-फर्स्ट अप्रोच के चलते मौजूदा समय में वे अपर मुख्य सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) के पद पर कार्यरत हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा आयुक्त और भोपाल गैस त्रासदी राहत कार्य जैसे संवेदनशील मामलों में भी उनके जनहित-प्रथम कार्यशैली के रिकॉर्ड को देखते हुए राज्य सरकार ने उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का भरोसा जताया है। अशोक बर्णवाल उन अधिकारियों से से एक हैं, जो अपने कार्यकाल के दौरान दो मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव भी रहे हैं। अगस्त 2016 में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपना प्रमुख सचिव बनाया गया तो 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तब कमलनाथ ने भी उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए अपना प्रमुख सचिव बनाए रखा। मुख्य सचिव पद पर स्थायी नियुक्ति होने के बाद अशोक बर्णवाल पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव तथा केन्द्र की मोदी सरकार की मंशा के अनुरूप मप्र के प्रशासन की गाढ़ी कुशलता से आगे हकने की जिम्मेदारी रहेगी। मोटो तौर वर्तमान सीएस अनुराग जैन और मुख्यमंत्री डॉ.यादव के बीच बेहतर तालमेल रहा है। अशोक बर्णवाल से भी यही उम्मीद रहेगी कि वो मप्र में विकास, निर्णय क्षमता में तेजी और सरकार के फैसलों का प्रभावी क्रियान्वयन कराने में सक्षम होंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बर्णवाल अच्छे अधिकारियों को सही जगह कैसे तैनात कराते हैं। उनके पास लगभग 1 साल का कार्यकाल रहेगा। काम अच्छा रहा तो आगे सारे विस्तार भी मिल सकता है। फिलहाल उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं।

नजरिया

कुमार कृष्ण

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



लोकतंत्र की पहचान केवल चुनावों से नहीं होती; उसकी असली शक्ति संवाद में निहित होती है। चुनाव सत्ता तय करते हैं, लेकिन संवाद समाज को जोड़ता है। जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने वाले नागरिकों का सामना बातचीत से पहले बैरिकेड, कंक्रीट की दीवारों, पुलिस बंदोबस्त और हिरासत से होने लगे, तब प्रश्न केवल कानून-व्यवस्था का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र की प्रकृति पर खड़ा हो जाता है। दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर वही दृश्य दिखाई दिया, जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति का स्थायी प्रतीक बन गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राजधानी की ओर बढ़े। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि खेती, बाजार और आजीविका को लेकर गहरी आशंकाएं थीं। लेकिन शंभू बाँर्डर पर उनका स्वागत संवाद से पहले सीमेंट के ब्लॉकों, लोहे के बैरिकेडों और भारी पुलिस बल से हुआ। इस बार घटनाक्रम केवल प्रतीकात्मक नहीं था। ‘देश बचाओ मोचा’ के आह्वान पर पंजाब के विभिन्न जिलों से हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने निकले। फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, मानसा और बठिंडा से किसानों के जत्थे शंभू सीमा तक पहुंचे, लेकिन हरियाणा सरकार ने सीमा को लगभग अभेद्य बना दिया। घग्गर नदी के पुलों पर भी कंक्रीट के अवरोध रख दिए गए। कई किसानों को अपने वाहन छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ा। किसान नेता सारवन सिंह पंडेर ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राजधानी में अपनी बात रखने से रोक रही है। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। कई किसान नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। यहीं से यह घटनाक्रम केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह जाता। संवाल यह है कि किसी लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर संवाद होना चाहिए या बैरिकेड?

सरकार का कहना है कि ये कदम कानून-व्यवस्था

सामाजिक विश्वास से तय हो आर्थिक विकास

भारत की कृषि को केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। देश के अधिकांश किसान दो-तीन एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका की कृषि विशाल व्यावसायिक फार्मों, उन्नत तकनीक और व्यापक सरकारी सहायता पर आधारित है। ऐसी असमान परिस्थितियों में खुली प्रतिस्पर्धा को लेकर किसानों की चिंता स्वाभाविक है।

बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं, जबकि किसान संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को सीमित किया जा रहा है। दोनों दावों के बीच भारतीय लोकतंत्र एक कठिन प्रश्न से जुड़ा रहा है—क्या असहमति अब प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है?

इस बार का आंदोलन केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या कर्ममाफी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौता है। किसान संगठनों की आशंका है कि यदि कृषि और डेयरी क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा दिए बिना यह समझौता लागू हुआ, तो सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में प्रवेश करेंगे। इससे सबसे बड़ा आघात उन छोटे और सीमांत किसानों को लगेगा, जो पहले ही बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितता से जुझ रहे हैं। भारत की कृषि को केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। देश के अधिकांश किसान दो-तीन एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका की कृषि विशाल व्यावसायिक फार्मों, उन्नत तकनीक और व्यापक सरकारी सहायता पर आधारित है। ऐसी असमान परिस्थितियों में खुली प्रतिस्पर्धा को लेकर किसानों की चिंता स्वाभाविक है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी है। वैश्विक व्यापार समझौते अवसर भी पैदा करते हैं। नए बाजार, कृषि निर्यात और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के विस्तार से किसानों को लाभ भी मिल सकता है। इसलिए मूल प्रश्न व्यापार समझौते का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि उसकी शर्तों की पारदर्शिता और कृषि हितों की सुरक्षा है।

यही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। यदि किसानों की आशंकाएं निराधार हैं तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कौन-से प्रावधान प्रस्तावित हैं। यदि कुछ जोखिम हैं तो उनके समाधान भी सार्वजनिक होने चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास गोपनीयता से नहीं, पारदर्शिता से बनता है।

बीते वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है। किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन पर सबसे पहले धारा 144 लागू

होती है, फिर बैरिकेड लगाते हैं, नेताओं को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद संवाद की बात होती है। लोकतंत्र का स्वाभाविक क्रम इसका उल्टा होना चाहिए। पहले बातचीत, फिर समाधान का प्रयास और अंत में आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक उपाय।

शंभू बाँर्डर अब केवल पंजाब और हरियाणा की सीमा नहीं रह गया है। 2020-21 के किसान आंदोलन से लेकर आज तक यह सरकार और किसानों के बीच भरोसे के संकट का प्रतीक बन चुका है। इतिहास बताता है कि किसान आंदोलनों का समाधान कभी पुलिस व्यवस्था से नहीं निकला; अंततः रास्ता बातचीत से ही निकला है।

भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखता है। मुक्त व्यापार समझौते उसकी आर्थिक रणनीति का हिस्सा हैं। लेकिन भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसी भी व्यापार समझौते का मूल्यांकन केवल निर्यात, निवेश और विकास दर के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि उसका प्रभाव खेत, किसान और गांव पर क्या पड़ेगा।दुनिया के विकसित देशों का अनुभव भी यही बताता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देश मुक्त व्यापार का समर्थन करते हुए भी अपने किसानों को संरक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह वैश्विक अवसरों और घरेलू कृषि सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे स्थापित करे।

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष लोकतांत्रिक है। किसानों की हर आशंका सही हो, यह जरूरी नहीं। सरकार का हर निर्णय गलत हो, यह भी आवश्यक नहीं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से तय होती है कि वह असहमति से कैसे संवाद करता है। सरकार की जिम्मेदारी केवल शासन करना नहीं, बल्कि विश्वास पैदा करना भी है। किसान संगठनों की जिम्मेदारी भी तथ्यों और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ अपनी बात रखना है।

दिल्ली की सीमाओं पर खड़े बैरिकेड केवल सड़कें नहीं रोक्ते; वे राज्य और समाज के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक भी बन जाते हैं। लोकतंत्र में यह दूरी जितनी

बढ़ती है, संवाद उतना ही कठिन होता जाता है। भारत की कृषि का प्रश्न केवल किसानों का प्रश्न नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता का भी प्रश्न है। इसलिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के सभी संभावित प्रभावों पर संसद, किसान संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के बीच खुली बहस होनी चाहिए। बड़े आर्थिक निर्णय व्यापक सामाजिक सहमति से ही स्थायी बनते हैं।

अंततः संवाल केवल एक व्यापार समझौते का नहीं है। संवाल यह है कि भारत किस तरह का लोकतंत्र बनाना चाहता है—वह जिसमें असहमति को सुरक्षा चुनौती माना जाए, या वह जिसमें विरोध को नीति सुधार का अवसर समझा जाए।

शंभू बाँर्डर से किसान घाट तक की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार कंक्रीट की नहीं, भरोसे की होती है। भरोसा टूटने लगे तो सबसे ऊंचे बैरिकेड भी व्यवस्था को स्थिर नहीं रख सकते। लेकिन यदि संवाद जीवित रहे तो सबसे कठिन मतभेद भी सुलझाए जा सकते हैं।

भारत यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके किसान स्वयं की स्थिरता केवल समझौतों से नहीं, सामाजिक विश्वास से तय होती है। खेत केवल अन्न नहीं उगाते; वे लोकतंत्र की जड़ों को भी सींचते हैं। उन जड़ों तक यदि संवाद का पानी नहीं पहुंचेगा, तो विकास की सबसे ऊंची इमारत भी अविश्वास की जमीन पर खड़ी रह जाएगी। इसलिए आज सबसे बड़ा संवाल व्यापार समझौते का नहीं, लोकतांत्रिक विश्वास का है। और इस संवाल का उत्तर बैरिकेडों से नहीं, बातचीत की मेज से निकलेगा।

जंतर मंतर प्रदर्शन

डॉ.संजीव कुमार

सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञ



एक क व्यंग्य के रूप में उपजी सोशल मीडिया द्वारा स्थापित कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज देश में सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इस सोशल मीडिया द्वारा उठाए गए संवाल और तूफान ने हमारे सामने तीन संवाल खड़े किए हैं। पहला जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कब तक अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे? दूसरा सत्ता में बैठे हुए लोग शिक्षा से कब तक मजाक करेंगे? और आखिरी, शिक्षित युवाओं के लिए सरकार कब संवेदनशील रहेगी? वर्तमान में जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा आंदोलन खड़ा किया गया है उसकी बुनियाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकान्त द्वारा दिए गये उस विवादित बयान से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था ‘कुछ युवा कॉकरोच (तिलचट्टों) की तरह हैं, जिन्हें अपने पेशे में कोई जगह या रोजगार नहीं मिलता। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।’ इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को समाज का ‘परजीवी’ भी कहा था। उनके इस बयान से देश भर के युवा आक्रोशित हो उठे। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान का कड़ा विरोध किया। दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने व्यंग्य के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। देखते ही देखते देश भर में हफ्ते भर के अंदर इसके भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा लोग फॉलोअर हो गए। 12 मई को नीट की परीक्षा खुद एनडीए द्वारा रद्द करने की घोषणा के बाद कुछ ही हफ्तों में देश भर से लगभग 12 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। इस घटना को कॉकरोच जनता पार्टी अपना मुद्दा बनती है और फिर अभिजीत दीपके अपने दो सहयोगियों सौव्य दास एवं

अनुराग रांका के साथ मिलकर 20 जून से जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा करते हैं। एक हफ्ते तक इनका आंदोलन देशभर में यह संदेश पहुंचाने में कामयाब होता है कि वर्तमान सरकार किस तरह से शिक्षा तथा रोजगार पर अपनी जवाब देही नहीं तय कर पा रही है। पूरा देश देख रहा है कि वर्तमान सरकार शिक्षा के मायने में हर स्तर पर लगातार असफल हो रही है। ऐसी स्थिति में भी अगर कुछ युवा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन-रात कड़ी परिश्रम करते हैं और जब कोई परीक्षा रद्द हो जाती है अथवा लीक हो जाती है तो इन 18 -19 साल के युवाओं की मनोदशा टूट जाती है।

अभी जंतर मंतर पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है युवाओं का, दरअसल वह गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा लिक को लेकर ही नहीं है, यह गुस्सा सरकार द्वारा लगातार भारतीय शिक्षा की स्थिति को खराब करने, नियुक्तियों में लगातार कमी, परीक्षा का समय पर नहीं होना, परीक्षाओं का टाल- मटोल करना, सरकार को खुद को कानून से ऊपर समझना, बुलफुडर से न्याय करना, दलितों पर देश में बढ़ते हमले, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार, प्रधानमंत्री का देश और दुनिया में देश की किरकरी करवाना, 12 साल में प्रधानमंत्री द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाना, और वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी इत्यादि कई मामले शामिल है जो अब ज्वाला बन चुकी है। सरकार को लग रहा था कि यह आंदोलन सोशल मीडिया द्वारा एक मामूली प्रदर्शन है, इसलिए वह लगातार इसकी उपेक्षा कर रही थी। 28 जून को जब प्रख्यात वैज्ञानिक एवं समाजसेवी सोनम वांगचुक इस आंदोलन के साथ

जुड़ जाते हैं तब इसकी गूंज देश के बाहर पहुंचने लगती है। न्यूयार्क लंदन और नीदरलैंड के शहरों से सोनम वांगचुक तथा कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में वहां भी धरने होने लगते हैं। 16 जुलाई को कुछ पुलिसों द्वारा अभिजीत दीपके के साथ बतमजी की जाति है जिसके लिए अभिजीत प्रशासन कर्मियों से रियायत की मांग करते हैं। 17 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर सोनम वांगचुक से मुलाकात करने जंतर मंतर



पहुंचते हैं। वहां आंदोलन में बैठे छात्राओं तथा सोनम वांगचुक की हालत देखकर वें द्रवित हो उठते है और सोनम वांगचुक तथा अभीजीत के सहयोगियों से पूछते है की आपके आन्दोलन को मजबूत करने के लिए कितने लोग चाहिए? आप 20 जुलाई को संसद मार्च कीजिए। अतः अभीजित के सभी सहयोगी 20 जुलाई को शांतिपूर्ण संसद मार्च की घोषणा करते इससे पहले 18 जुलाई को सुबह 4 बजे बर्बरता से वांगचुक जी को सादे कपडे में दिल्ली पुलिस के लोग उठा ले जाते है।

सरकार द्वारा करवाया गया यह घृणित कार्य इस आंदोलन में जलते हुए हवन में घी का काम करता है। देशभर के युवाओं का गुस्सा सरकार के खिलाफ और उग्र हो उठता है। अतः 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा की होते ही सरकार 19 जुलाई को रात से ही दिल्ली के चारों तरफ पहरेदारी मजबूत करने लगती है। पर संसद मार्च इतना विशाल इतना ताकतवर होगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। इस संसद मार्च के तीन प्रमुख चेहरे जो देश और दुनिया भर में प्रमुखता से छाप रहे उसमें अभिजीत के बाद पहला नाम चंद्रशेखर और दूसरा फ़िल्म कलाकार प्रकाश राज का आता हैं। यह तीनों लोग पूरे दिन संसद मार्च के समय दिल्ली में हो रहे लगातार बारिश और आंधी के बीच पुलिस की लाठियों के सामने डटे रहे। चन्द्रशेखर अभी भी संसद भवन के बाहर खुले आसमान के नीचे एक बोरे का तिरपाल बनाकर आन्दोलन को मजबूत किए हुए है। इस बीच दिल्ली पुलिस के द्वारा इन विद्यार्थियों, शोधार्थियों, समाजसेवियों से जो अभद्रता तथा हिंसात्मक कार्रवाई की गई उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हैं। आन्दोलन में जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी और नेता डिम्पल यादव पूरा दिन बच्चों के साथ रहकर उन्हें साहस प्रदान करते दिखे थे। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जिस प्रकार से कायरतापूर्ण बिना वर्दी ,बिना नेम प्लेट के अज्ञात लोगों का सहयोग लिया है वह सरकार की मंसा पर बड़ा संवाल हैं।

इस पूरे आंदोलन को जो जान थी वह इसके दो नारों में शामिल है इंकलाब जिंदाबाद और जय भीम। इस पूरे आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि आज देश दो विचारों में बंटा हुआ है पहला जय श्री राम (राजनीतिक नारा) दूसरा जय भीम (तार्किक राष्ट्र)। एक दशक पहले तक अंबेडकर और जय भीम का नारा सिर्फ दलित समुदाय ही लगाते थे. इसलिए अंबेडकर की राजनीति और उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को सिर्फ दलित राजनीति तक ही समेट कर देखा जाता था। पर जब से राजनीति में चंद्रशेखर नाम का उदय हुआ है देश ही नहीं पूरी दुनिया में जय भीम का नारा अब हर वह व्यक्ति लगाता है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, समानता और बंधुता में विश्वास रखता है, एक तार्किक और नैतिक राष्ट्र चाहता है। इसलिए आज अम्बेडकरवाद यानि लोकतंत,अम्बेडकर यानि सामाजिक न्याय,अम्बेडकर यानि स्त्री शिक्षा,अम्बेडकर यानि तार्किक शिक्षा, अम्बेडकर यानि समता,अम्बेडकर यानि समानता, अम्बेडकर यानि नैतिक नागरिक,अम्बेडकर यानि पाखंड से मुक्ति,अम्बेडकर यानि सत्ता से संवाल बन चुका है .इसलिए जो भी मानवता में यकीन रखता है वो अम्बेडकरवादी है।

इस आंदोलन में पहले दिन से ही इंकलाब और जय भीम के नारे गुंजते दिखाई दिए हैं। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोगों ने कई बार इस आंदोलन को दिशाहीन करने का प्रयास किया। युवाओं को जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया परंतु अंततः वें असफल हुए। आज के युवा अब समझ चुके हैं कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिसमें उनकी और राष्ट्र दोनों की उन्नति तय हैं। इसलिए यह जेन जी अब किसी धार्मिक नारे के आगे अपना भविष्य दाव पर नहीं लगाने वाली क्योंकि वे शिक्षा का महत्व अब समझ चुके हैं। इसीलिए अंबेडकर ने कहा था ‘शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिणा वह उतना दहाड़ेगा’ और हमारे मूर्ख राजनेता इसी दहाड़ से डरते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPJIN/ 2003/ 10923,

Ph.No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विवाद लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

अभिलक्ति

संजीव शर्मा



हाल ही में विश्व इमोजी दिवस मनाया गया । यानी उन पीले-पीले गोल चेहरों का दिन, जिन्होंने दुनिया की हजारों भाषाओं को चुनौती दे दी है। कभी शब्दों के सहारे रिसते बनते थे, अब एक 🧡🧡🧡🧡🧡 तय कर देता है कि सामने वाला खुश है, नाराज है या केवल औपचारिकता निभा रहा है। किसी समय हम सभी चिट्ठी में लिखते थे कि प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र पाकर हृदय गदगद हो उठा। आज इस भाव को एक 🧡 में समेट दिया गया है। कभी किसी की उपलब्धि पर हम खुलकर लिखते थे कि हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।अब बस... 🧡🧡🧡 और काम खत्म। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भाषा पुस्तकों/ शब्दकोश/अखबारों में कैद हो गई है और बातचीत इमोजी कीबोर्ड पर आ बसी है। सोशल मीडिया में तो बिना इमोजी के गुजारा ही नहीं है। सारा सुख-दुख बस चंद कार्टून मुमा चेहरों में सिमट गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इमोजी ने उम्र का, अनुभव का,रिश्तों का अंतर भी लगभग मिटा दिया है।

इमोजी, मतलब भावना ने भाषा की छुट्टी कर दी

दस बारह साल का बच्चा भी 🧡 भेजता है और सत्तर पचहत्तर वर्ष के दादाजी भी। दोनों का हँसना अब एक ही चेहरे से व्यक्त होता है। दुख भी एक 🧡 है, गुस्सा 🧡 भी और प्यार भी 🧡 । भावनाओं की विविधता चंद चित्रों में सिमटती जा रही है।

इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है। पहले किसी की बात पसंद आती थी तो हम लिखते थे कि आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ।असहमत होती तो तर्क दिए जाते थे..विषय पर चर्चा/बहस और तर्क विवर्क होते थे। अब पूरी बहस का निष्कर्ष केवल दो बटन है या । कई बार तो समझ ही नहीं आता कि सामने वाले ने पोस्ट पढ़ी भी है या केवल अंगुठा दिखाकर आगे बढ़ गया। कुल मिलाकर संवाद की जगह प्रतिक्रिया ने ले ली है, और प्रतिक्रिया भी इतनी छोटी कि उसमें विचारों की कोई जगह नहीं बचती।

बाकी कई बार तो रिएक्शन (प्रतिक्रिया) का स्थान भी व्यूज (views) ले जाते हैं और लिखने/पोस्ट करने वाले की पूरी मेहनत व्यूज की संख्या में सिमट जाती है। अब तो सोशल मीडिया में लोकप्रियता आंकने का पैरामीटर व्यूज ही रह गया है और व्यूज के आधार पर कमाई ने तो सारे मनोभाव/क्रिया प्रतिक्रिया को व्यूज में

समेट दिया है।

इमोजी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ भी रख सकता है। किसी के लिए 🧡 शिष्ट मुस्कान है, तो किसी के लिए 🧡 व्यंग्य। किसी के लिए ठहका है, तो किसी के लिए मजाक उड़ाना। यानी भाषा, जो स्पष्टता लाती थी, उसकी जगह कई बार अनुमान ने ले ली है। वैसे भी, आमतौर पर कुछ नियमित इस्तेमाल होने वाले इमोजी को छोड़कर अधिकतर लोगों को इन इमोजी के सही अर्थ भी नहीं पता होता। इसलिए, वे बिना अर्थ जाने भाव का अनर्थ करते रहते हैं।

इमोजी ने सबसे गहरा असर बच्चों की शब्द-सम्पदा पर डाला है। अब जब हर भावना के लिए उनके पास चित्र मौजूद हैं तो उन्हें नए शब्द सीखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है।आश्चर्यचकित/विस्मित/ आह्लादित/ व्यथित/ आक्रोशित जैसे सुंदर एवं अर्थपूर्ण शब्द धीरे-धीरे चंद चेहरे के पीछे छिपते जा रहे हैं।

हम सभी जानते हैं भाषा में हर शब्द का उपयोग के मुताबिक अर्थ होता है, उनमें अर्थ के साथ गूढ़ अर्थ भी छिपा होता है जिसे अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन कहते

हैं लेकिन इमोजी की बस एक भाषा/अर्थ होता है। विकास का एक पहलू यह भी है कि भाषा जितनी समृद्ध होती है, सोच भी उतनी ही गहरी होती है। शब्द घटते हैं तो विचार भी घटने लगते हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इमोजी बुरे हैं और उनको व्यवहार से निकाल फेंकना चाहिए। इमोजी उपयोगी हैं और कई बार संवाद को सहज, तेज़ और कई बार अधिक आत्मीय बनाते हैं। इसलिए समस्या उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि उन्हें भाषा की तरह उपयोग करना है क्योंकि वे भाषा के सहायक बन सकते हैं लेकिन भाषा के विकल्प नहीं बन सकते और इसे किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए, इस तरह के स्वघोषित दिवसों पर हमें अपने आप से एक संवाल जरूर करना चाहिए कि क्या हम या हमारे बाद की पीढ़ियों में भाषा का स्थान इमोजी को सहजता से सौंपना उचित है और इससे भाषा का भविष्य कहां पहुंचेगा? एक बात बिकटूल स्पष्ट है कि जिस दिन हमारी पूरी बातचीत केवल 🧡🧡🧡🧡🧡 तक सीमित रह जाएगी, उस दिन संवाद भी मौन हो जाएगा क्योंकि इमोजी चेहरे दिखाते हैं, लेकिन शब्द मन की पूरी तस्वीर बनाते हैं।

नशाखोरी

डॉ. घनश्याम बटवाल

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।



देश के युवा वर्ग में इन दिनों नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है तथा उसी प्रकार नशे से हो रही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए युवाओं को नशे से बचाने के लिए पहल करनी होगी, ताकि युवा सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर युवा शक्ति नशे की चपेट में आ रही है, तो नशा रूपी राक्षस को किस तरह समाप्त किया जा सके, इस विषय में समाज को गंभीर चिंतन करना होगा और यह सामूहिक जिम्मेदारी है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विभिन्न राज्यों में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों की दर अलग-अलग है, लेकिन एक बात साफ है कि नशे का जो प्रचलन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इसके कारणों में मुख्य रूप से निष्क्रिय जीवन शैली, युवा वर्ग को उचित मार्गदर्शन का अभाव, पारिवारिक कलह, माता-पिता द्वारा बच्चों की तरफ ध्यान न देना, गलत संगत, अवसाद, तनाव, प्रेम में हताशा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा अति महत्वाकांक्षी होना भी है।

हाई प्रोफाइल जीवन शैली की लालसा, नशे को शान का प्रतीक समझना, नशे की उपलब्धता तथा पहुंच आसान होना एवं अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी नशे की लत के कारण हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग के कारण आज का नौजवान नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। यह भी एक कारण बन रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स व अन्य प्रतिक्रियाओं से डोपामाइन नामक रसायन का स्त्राव होता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का अहसास कराता है। इसका अत्यधिक प्रयोग हमें वास्तविक जीवन से दूर करता जाता है। सोशल मीडिया की तरह जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, शराब अफीम या कोई नशा करता है, तब भी डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जो उसे खुशी का अहसास देता है। ऐसे में खुशी पाने के लिए व्यक्ति को ज्यादा नशे की जरूरत पड़ती है और व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो जाता है।

मानव मस्तिष्क की रासायनिक प्रणालियों में भी परिवर्तन आता है। जब बच्चों युवाओं के मस्तिष्क में ये परिवर्तन आते हैं, तो नशे प्रभावित बच्चों में चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई, बच्चों युवाओं की जीवनशैली में परिवर्तन, घर में चोरी आदि घटनाएं नशे का दुष्परिणाम दर्शाती हैं।

समाज में नशाखोरी की लत से दिग्भ्रमित होते युवा

नशे भी कई तरह के होते हैं। किसी लक्ष्य को पाने का जुनून भी एक प्रकार से नशा ही है। जैसे परीक्षा में अट्ठल आना, खेल में विजेता होना, लक्ष्य को हासिल करना, दायित्वों को सबसे पहले पूर्ण करना या गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने जैसे जुनून। नशे में डूबकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना सकारात्मक पक्ष है। लेकिन, नशा करने की आदत लगना अनुचित है, जो आजकल लगातार बढ़ रहा है। आमतौर पर उस नशे की आदत जो मादक द्रव्यों, सिंथेटिक ड्रग्स, शराब, स्मैक और हेरोइन आज बर्बादी के कारण बन रहे हैं। नशे का नया माध्यम ड्रग्स हैं, जो युवाओं को आकर्षित कर रहा है।



अब तो युवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मालवा-मेवाड़ और हाड़ौती के एक दर्जन जिलों में अफीम, हेरोइन, स्मैक के अलावा एमडी का प्रचलन बढ़ रहा है, यह घातक है पर नशा दे रहा है। एमडीएमए, एलएसडी, कोकीन आदि कैप्सूल, क्रिस्टल पाउडर और लिक्विड रूप में मिल रहे हैं। स्कूलों, कॉलेज आदि के आसपास रासायनिक ड्रग्स बिस्कूट, चॉकलेट और ड्रिंक के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस और प्रशासन ही नहीं समाज और पेरेंट्स को भी

इस बात का विशेष ध्यान करना होगा कि बच्चे किशोर इन सबसे दूर रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बच्चे और नौजवान जो कुछ भी देखते हैं, उसके प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यह आयु वर्ग साथियों के प्रभाव और दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। संतान की परवरिश में कमी, बच्चों को बिगाड़ने में माता-पिता भी दोषी होते हैं। कई बार माता-पिता अपने बच्चों को सारे सुख एवं सुविधाएं बिना

मेहनत के उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका बच्चा सामाजिक जिम्मेदारी होने से असफल होता है। इसका खामियाजा उन्हें उनके बच्चों द्वारा गलत संगत में पड़कर, व्यसन होने के कारण भुगतना पड़ता है। अतः जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को वास्तविक जिंदगी में आने वाले संघर्षों और कठिनाइयों के बारे में भी बताएं। आधुनिक जीवन शैली में बच्चों युवक युवतियों को कई तरह के तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जैसे

कि परीक्षा का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और परिवार की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा ये तनाव बच्चे और युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। बच्चों को अनावश्यक दबाव या तनाव से बचाने के लिए माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों किशोर आयु वर्ग की बातों को भी ध्यान एवं धैर्य से सुनें तथा उन्हें यह महसूस करने दें कि उनकी राय मायने रखती है। गत वर्षों में यह तथ्य बताते हैं कि अवैध मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी में एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए आरोपियों में अधिकांश किशोर से युवा आयु वर्ग 15 से 30 उम्र के सबसे अधिक है। आर्थिक रूप से ऐसे किशोर युवा आरोपी अवैध मादक द्रव्य पदार्थों को इधर से उधर पहुंचाने वाले कैरियर का काम नकदी प्राप्त कर करते पाए गए हैं और इस आकर्षण के साथ वे भी मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हुए नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। यह समाज, सरकार के साथ समाजशास्त्रियों के विवेचन का विषय है।

बहरहाल, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने तथा इनके नेटवर्क को नष्ट करने की कोशिश में हैं। गत वर्ष की तरह यह दूसरी बार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई अपना व्यक्ति नशे की लत से ग्रसित है तो उसे इस अंधकार से दूर करने के लिए धैर्य के साथ काउंसलिंग करते हुए अनुकूल वातावरण दें, ताकि वह इस व्यसन से बाहर आ सके और निजात पा सके। उसका नशा मुक्ति केंद्र पर उपचार कराये। निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। मंदसौर, नीमच में ऐसे सैकड़ों युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकाला गया है। साथ ही प्रदेश भर में तीर्थ और धार्मिक स्थानों पर शराब बंदी व्यवस्था लागू की गई, पर यह पूरी तरह सफल नहीं हो रही है। इस अभियान में जुटे पुलिस बल और,आबकारी विभाग, समाज जनों को शराबबंदी को लागू करने में विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है।

वक्रोक्ति

सूर्यदीप कुशवाहा

लेखक व्यंग्यकार हैं।



शासन प्रशासन की भाषा जब बदलने लगती है, तो वह सबसे पहले लाठी का रूप लेती है। लोकतंत्र में संवाद का स्थान अवसर लाठियां ले लेती हैं और तर्क का स्थान छत्रों की छतियां। यह आज सबसे बड़ा और कड़वा सच बन चुका है।जब भी देश के युवा अपने अधिकारों, रोजगार या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उनका स्वागत गुलाब के फूलों से नहीं, बल्कि पुलिस की मजबूत और तेल पिलाई हुई लाठियों से किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सरकारी व्यवस्था में लाठी और छत्र की छाती का एक अटूट, शाश्वत और गहरा रिश्ता बन चुका है। छत्र इधर किसी विसंगति या धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी छाती फुलाते हैं, उधर प्रशासन उनकी छाती का नाप लेने के लिए लाठियां भांजना शुरू कर देता है।लाठी की अपनी एक अलग ही फिलॉसफी है। लाठी निरक्षर होती है, उसे यह नहीं पता होता कि वह जिस छाती पर बरस रही है, उसमें

पुलिस की लाठी और छात्रों की छाती

छत्र इधर किसी विसंगति या धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी छाती फुलाते हैं, उधर प्रशासन उनकी छाती का नाप लेने के लिए लाठियां भांजना शुरू कर देता है। लाठी की अपनी एक अलग ही फिलॉसफी है। लाठी निरक्षर होती है, उसे यह नहीं पता होता कि वह जिस छाती पर बरस रही है, उसमें देश का भविष्य धड़क रहा है। लाठी को तो बस आदेश का पालन करना आता है। कमाल की बात यह है कि जब छत्र परीक्षा में पेपर लीक होने, कट-ऑफ में गड़बड़ी होने या फीस वृद्धि के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं, तो वे राष्ट्रविरोधी मान लिए जाते हैं।



देश का भविष्य धड़क रहा है। लाठी को तो बस आदेश का पालन करना आता है। कमाल की बात यह है कि जब छत्र परीक्षा में पेपर लीक होने, कट-ऑफ में गड़बड़ी होने या फीस वृद्धि के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं, तो वे राष्ट्रविरोधी मान लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, उन पर लाठियां बरसाने वाली पुलिस को कानून व्यवस्था का सच्चा रक्षक घोषित कर दिया जाता है। छत्र की छाती पर पड़ने वाला हर एक प्रहार दरअसल उसकी उम्मीदों और हौसलों पर प्रहार होता है। समसामयिक दौर में विडंबना देखिए कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में सब कुछ स्मार्ट हो चुका है—स्मार्टफोन, स्मार्ट क्लास और स्मार्ट सिटी। लेकिन छात्रों को संभालने का तरीका आज भी वही पुराना, घिसा-पिटा और क्रूर है। जब युवा रोजगार की मांग करते हैं, तो उन्हें लाठी चार्ज का मुफ्त पैकेज दिया जाता है। प्रशासन का मानना है कि

युवाओं के दिमाग का रास्ता उनकी पीठ और छाती से होकर गुजरता है। जितनी जोर से लाठी पड़ेगी, उतनी ही जल्दी छत्र को अपनी ‘गलती’ का अहसास होगा और वह वापस अपने कमरों में जाकर चुपचाप बैठ जाएगा।छात्रों की छतियां भी गजब की हैं। वे गोलियों और लाठियों के सामने तनकर खड़ी हो जाती हैं। इन छतियों के भीतर डिग्रियां, सुनहरे सपने और अपने बूढ़े माता-पिता की आंखों की उम्मीदें छिपी होती हैं। लेकिन जब पुलिस की लाठी इन पर बरसती है, तो वे सपने पल भर में बिखर जाते हैं। नेताओं के भाषणों में युवा हमेशा ‘देश का भविष्य’ होते हैं, लेकिन सड़कों पर आते ही वे द्रोही या हुड़दंगी बन जाते हैं। यह व्यंग्य नहीं, बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। लाठियों के बल पर युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश यह दर्शाती है कि व्यवस्था संवाद करने की अपनी क्षमता खो चुकी है। जब तक छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उनकी छतियों को लाठियों से नापा जाता रहेगा, तब तक लोकतंत्र का यह चेहरा बदरंग ही दिखेगा। लाठी सिर्फ शरीर पर चोट नहीं करती, वह पूरे समाज के विवेक और चेतना को घायल कर देती है।

अनुभव

डॉ. तेजी ईशा

लेखक एसजीटी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में विभागाध्यक्ष और सहायक अध्यापक हैं।



वैसन नहीं मिल पा रहा, इसलिए लिख रही हूँ। सुबह, दोपहर, शाम और रात—हर वक़्त वही तस्वीरें, वही वीडियो आँखों के सामने घूमते रहते हैं जो जंतर-मंतर से उठे और सोशल मीडिया के रास्ते हमारे भीतर कहीं गहरे जाकर अटक गए। बिल्कुल एक कॉटेंट की तरह। जितना उन्हें भूतने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वे भीतर धँसते जाते हैं। 20 जुलाई 2026। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन। काला दिन इसलिए नहीं कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं पर लाठियाँ बरसाईं। उन्हें घसीटा, थप्पड़ मारे, ज़मीन पर पटका, बाल पकड़कर खींचा और अपराधियों की तरह उठाकर गाड़ियों में भर दिया।

काला दिन इसलिए भी नहीं कि देश की राजधानी में, दिन के उजाले में, संसद और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर लोकतांत्रिक विरोध को पुलिसिया बूटों से कुचलने की कोशिश हुई। इस देश ने पहले भी आंदोलनों पर लाठियाँ देखी हैं। सत्ता का दमन भी नया नहीं है। लेकिन 20 जुलाई का दिन इसलिए काला है क्योंकि उस दिन एक लड़की के साथ जो हुआ, उसने सिर्फ़ कानून नहीं, ईंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। एक वीडियो में दिखता है कि डर के मोरे भाग रही एक लड़की को एक पुलिसकर्मी पकड़ने की

कोशिश करता है। उसके शरीर को जिस तरह छुआ जाता है, वह किसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं लगती। फिर दूसरा वर्दीधारी अधिकारी, जिसके कंधे पर सितारे सजे हैं, उसके शरीर के साथ जिस तरह का व्यवहार करता दिखाई देता है, वह किसी भी संवेदनशील ईंसान की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। उस क्षण वर्दी कानून का प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि भय का चेहरा बन जाती है। उस दिन ऐसा लगा मानो दो वर्दीधारी लोग मिलकर एक लड़की की गरिमा को सरेआम रौंद रहे हों। अगर आसपास कैमरे न होते, अगर सैकड़ों मोबाइल फोन उस घटना को रिकॉर्ड न कर रहे होते, अगर सोशल मीडिया गवाह न बनता, तो शायद इस घटना की कहानी भी उन अनगिनत

कहानियों की तरह दफ़न कर दी जाती, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। आप कुछ देर के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भूल

जाइए। शिक्षा व्यवस्था पर बहस भी भूल जाइए। यह भी भूल जाइए कि वर्षों से शिक्षा का बजट घटने की शिकायतें उठती रही हैं। राजनीति की

बहसें कल भी होंगी, संसद भी चलेगी, टीवी स्टूडियो भी सजेंगे। लेकिन क्या हम यह भूल सकते हैं कि लोकतंत्र की

राजधानी में अपने अधिकारों की माँग कर रही एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जिसे देखकर पूरा देश सिरहा गया? क्या हम यह भूल सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना, मुंबई और नागपुर तक अपने हक के लिए सड़कों पर निकले युवाओं को अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है, लड़कों के हाथ-पैर तोड़े जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में असहमति अब इतना बड़ा अपराध हो गई है कि उसका जवाब लाठी, बटूर और अपमान से दिया जाए? शायद हम सब भूलना चाहते हैं। शायद यह हमारी

मानसिक थकान है। शायद हर दिन आने वाली नई खबरें हमें पुरानी त्रासदियों से दूर धकेल देती हैं। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो स्मृति से मिटते नहीं। वे हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाते हैं।

जंतर-मंतर से आई वे तस्वीरें और वीडियो भी वैसी ही स्मृतियाँ हैं। वे केवल एक दिन की खबर नहीं हैं। वे आने वाले वर्षों तक हमें याद दिलाती रहेंगी कि लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ राज्य के व्यवहार में जीवित रहता है। और जिस दिन वर्दी नागरिक की सुरक्षा के बजाय उसके भय का कारण बन जाए, उस दिन सवाल सिर्फ़ पुलिस पर नहीं, पूरे लोकतांत्रिक तंत्र पर उठता है। सालों बाद शायद लोग इस आंदोलन की मीमें भूल जाएँ। शायद तारीख भी याद न रहे। लेकिन एक लड़की की आँखों में दिखता वह डर, सड़क पर बिखरी उसकी असहायता और वर्दी की आड़ में दिखाई देती वह क्रूरता—ये दृश्य इतिहास से आसानी से मिटने वाले नहीं हैं।

वे बार-बार लौटेंगे। हमें झकझोरेंगे। और पृष्ठे—क्या हमने सचमुच ऐसा भारत बनाने का सपना देखा था?

नगर के समस्त वार्डों की राजस्व वसूली समीक्षा,लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर कार्रवाई के निर्देश

सोहागपुर। नगर पंचायत परिषद परिसर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद धर्मेन्द्र शर्मा ने नगर के समस्त 15 वार्डों के वसूलीकर्ताओं की बैठक में नगर पंचायत परिषद की राजस्व वसूली की वाईवार समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रत्येक वार्ड की मांग के विरुद्ध में वसूली की प्रगति, लॉबित मांग एवं वसूली की स्थिति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व वसूली की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने



पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने समस्त वसूलीकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने आवंटित वार्डों में शत-प्रतिशत वसूली हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर नियमानुसार वेतन कटौती एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही समस्त वसूलीकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे लॉबित मांग की वसूली हेतु बकायादारों से नियमित संपर्क स्थापित कर प्रभावी वसूली अभियान संचालित करके आगामी अवधि में वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा में जिन वसूलीकर्ताओं की वसूली प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार वेतन कटौती एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही समस्त वसूलीकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे लॉबित मांग की वसूली हेतु बकायादारों से नियमित संपर्क स्थापित कर प्रभावी वसूली अभियान संचालित करके आगामी अवधि में वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

जून माह में टाइम ऑफ डेटैरिफ के तहत 8 लाख 70 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 11 करोड़ 14 लाख 20 हजार रुपये की छूट

भोपाल/ ग्वालियर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जून माह लाभदायक रहा। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डेटैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसी के तहत जून- 2026 में कंपनी कार्यक्षेत्र के 8 लाख 70 हजार 683 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों में 11 करोड़ 14 लाख 20 हजार रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला। इनमें भोपाल रीजन के 7 लाख 19 हजार 500 उपभोक्ताओं को 8 करोड़ 88 लाख 56 हजार रुपये तथा ग्वालियर रीजन के 1 लाख 51 हजार 183 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 25 लाख 64 हजार रुपये की छूट प्रदान की गई।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री श्रद्धी गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगावाएं। स्मार्ट मीटर न केवल ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण रखने और आर्थिक बचत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि टाइम ऑफ डेटैरिफ के तहत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) बिजली उपयोग करने पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा श्री कैलाश कुमार चौधरी, प्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) से संपर्क कर सकते हैं।

खेत के कमरे में जुआ फड़ पर छापा, 15 लोग गिरफ्तार पुलिस ने जब्त किये ताश के पत्ते और 90 हजार रुपए

बैतूल। थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ फड़ पर दबिश देकर 15 आरोपियों को रो हाथ गिरफ्तार किया है। 22 जुलाई को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन कर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झाडेगांव में आरोपी बंटी करोच के खेत में बने कमरे में ताश पत्तों से हार-जीत का जुआ चल रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके से ताश पत्तों से जुआ खेलते हुए कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से एक ताश की गड्डी एवं कुल नगदी 90,500 जस की गई। पुलिस ने इस दौरान जुआ खेलते हुए सौरभ पिता शिवकुमार, बंटी पिता मंगल, अजयसिंह पिता स्व. इलराज, शरद पिता मदनलाल, निलेश पिता राधाकृष्ण, पुष्परंग पिता रामसिंह, यश पिता गोविंद, अखिलेश पिता पारसनाथ, अजीत पिता अशोक, अंकित पिता स्व. रामदास, कमलेश पिता दयाराम, कपिल पिता कृष्णकांत, नितिन पिता कृष्णकुमार, सुदेश पिता स्व. रमेश और अशोक पिता अनिल को पकड़ है। सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उनि बसंत अह्के, उनि राकेश कुमार सरयाम, सजिन राजेश मालवीय, सजिन अरुण यादव, प्रआर. तरुण पटेल, प्र.आर. शिवकुमार उड्के, प्रआर. रामदास, प्र.आर. दीपक कटियार, आर. नितिन, आर. पुष्पराज, आर. प्रदीप, आर. अनिल बैलवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

जनपद

राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले पर संसद में सार्थक चर्चा की बजाय बच्चों को गुमराह कर रहे

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बरख़ोगी केंद्र सरकार : हेमंत खण्डेलवाल

आखिर संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता छात्रों के संवेदनशील विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार संसद में चर्चा के लिए जब तैयार है, तब भी राहुल गांधी चर्चा करने को तैयार नहीं है। आखिर राहुल गांधी संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की मंशा नीट पर चर्चा करने की नहीं, छात्रों को गुमराह कर अराजकता फैलाने की है। मैं मानता हूँ कि छात्रों और छात्रों से जुड़े विषयों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छात्र भी यही चाहते हैं कि इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिस नियम के तहत संसद में चर्चा करानी हो, जितनी देर तक चर्चा करानी हो, नीट और उससे जुड़े हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए केन्द्र सरकार तैयार है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ही चर्चा करने से भाग रहे हैं।

पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, सॉल्वर गैंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग और अन्य अनुचित तरीकों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। बॉम्बे, कलकता, दिल्ली और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने वाली हैं। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी, ताकि जांच और ट्रायल में देरी न हो और जल्दी फैसला आ सके। विशेष अदालतों के गठन से न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होगी,

बल्कि सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और पुख्ता होगी। साथ ही भविष्य में पेपर लीक और संगठित नकल जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है और जल्द ही 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

परीक्षा को लीक-प्रूफ बनाने के लिए कड़े कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विपक्ष के साथ मिलकर संसद में नीट और उससे जुड़े हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है। परीक्षा को

लीक-प्रूफ बनाने के लिए कई कड़े कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल संसद को बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, कामकाज नहीं होने देना चाहते। केंद्र सरकार चाहती है कि विपक्ष के पास भी यदि नीट पेपर लीक को लेकर कोई सुझाव है तो सदन में चर्चा कर उसे बताए, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों की मंशा युवाओं को गुमराह करना है। जनता द्वारा बार-बार नकारी गई कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल छात्रों के मुद्दे पर भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारी सरकार छात्रों को किसी भी स्थिति में बदनाम नहीं होने देगी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई परंतु हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने दर्जनों गिरफ्तारियां कराने के साथ एक महीने में तीन लीक-फ्फस परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा का बजट केवल 8225 करोड़ था, वहीं वर्तमान में यह बजट बढ़कर 1.39 लाख करोड़ रूपए हो गया है। एम्स, आईआईटी, टेक्निकल कॉलेज सहित अधिकांश महाविद्यालयों में छात्रों को अधिक से अधिक प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए सीटों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पेपर लीक जैसे घटनाओं के स्थायी समाधान के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

नशा एक ऐसा जहर है, जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है: प्राचार्य विवेक तिवारी

सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी के विद्यार्थियों ने नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान चलाया

बैतूल। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी में बुधवार विद्यार्थियों ने दोपहर पश्चात नशामुक्ति अभियान ,नशे के दुष्प्रभाव के अंतर्गत छात्र/छात्राओं ने गीत,भाषण,नाटक जन जागरूकता रैली के माध्यम से एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी। चौकी प्रभारी आशीष कुमरे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खारमुसे के निदेशन में एवं



एसडीओपी प्रियंका करचाम, थाना प्रभारी रानीपुर बबीता धुवें के मार्गदर्शन में सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी के 800 छात्र/छात्राओं को नशामुक्ति पर समझाइश ,जन जागरूकता संदेश दिया वही छात्रों को घर घर जाकर नशामुक्ति अभियान चलाने को कहा। प्राचार्य विवेक तिवारी ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया वहीं नशीले पदार्थों का सेवन एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति, परिवार और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। उन्होंने नारे के माध्यम से कहा हमारा है यही संदेश नशा मुक्त हो मध्यप्रदेश किसी भी चीज का नशा व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है बल्कि अपराधों में वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण है इस गंभीर समस्या से समाधान और एक स्वस्थ एवं शान मुक्त समाज के निर्माण के लिए नशे से दूरी है जरूरी एक व्यापक नशा मुक्ति जन जागृति अभियान पूरे मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है उन्होंने विद्यालयीन छात्र/ छात्राओं को अपने आसपास नशा करने वाले व्यक्तियों को समझाइस देकर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की। वही यह अभियान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से ही सफल हो सकता है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर छात्र/छात्राओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान घोड़ाडोंगरी चौकीप्रभारी आशीष कुमरे, प्रधान आरक्षक देवेंद्र प्रजापति, एवं सांदीपनि विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।



बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं सेवाओं की प्रगति की जांचकारी ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकीय सेवाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ.सोनवणे ने जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थानों में रक्त की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों से ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली कर्ताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विकासखंडों के बीएमओ एवं चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए कि जरूरतमंद मरीजों को शासन की व्यवस्था के अनुसार समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी भी स्टॉफ नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा ब्लड दिलाने के नाम पर मरीज या उसके परिजनों से पैसे लेने की शिकायत प्राप्त होती है, तो

संबंधित के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रभात पट्टन क्षेत्र में एएनसी पंजीयन की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने सभी बीएमओ को निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर एएनसी पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा पंजीयन के साथ ही उन्हें निर्धारित सभी स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मॉडरेट और सीवियर एनीमिक गर्भवती महिलाओं के आईडेंटिफिकेशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने आमला, आठनेर, मुलताई में कम प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीएमओ को निर्देश दिए कि ऐसी गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार तथा फॉलोअप सुनिश्चित किया

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा इंडवशन प्रशिक्षण

बैतूल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर 40 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 08 दिवसीय इण्डक्शन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन 19 जुलाई से कार्यालय सहयक आयुक्त आदिवासी विभाग के मीटिंग हॉल में किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 26 जुलाई तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में परियोजना अधिकारी बैतूल ग्रामीण निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा आंगनवाड़ी एवं परियोजना स्तर पर समन्वय कैसे करें तथा आंगनवाड़ी से अपेक्षाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है। परियोजना अधिकारी चिचोली चयेन्द्र बुईकर, परियोजना अधिकारी अर्चना तिवारी तथा प्रभारी परियोजना अधिकारी आठनेर रंजीता जोशी द्वारा ब्लॉक स्तर पर समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्यों में आंगनवाड़ी से अपेक्षाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह प्रभारी परियोजना अधिकारी खेत यादव द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं स्वीकृति संबंधी जानकारी दी जा रही है। पर्यवेक्षण बैतूल ग्रामीण श्रीमती श्वेता वाल्म्वे तथा पर्यवेक्षक आमला द्वारा सुश्री भावना चौधरी लाडली लक्ष्मी योजना के हिराग्राही आवेदन की प्रक्रिया, स्वीकृति एवं आवश्यक अभिलेखों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जाने की खबरें सामने आई हैं, जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हैं। जापन में कहा गया कि भारतीय नागरिक प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने, विरोध प्रदर्शन करने और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देना है। ऐसे में जनता और युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाना लोकतंत्र की मूल भावना पर गंभीर आघात है। कांग्रेस ने कहा कि देश का युवा शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में

की स्वतंत्रता का अधिकार देना है।

पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता जता रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों, वरिष्ठ नेताओं और छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर अनावश्यक बल प्रयोग पर रोक लगाने, छात्रों की शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान करने तथा नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी जापन के माध्यम से की गई।



जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यह घटना 19 जुलाई की रात अखतलाड़ा खेड़ी स्थित शिव शक्ति सेल्स पेट्रोल पंप पर हुई थी। यहां कर्मचारी राजेश शेषकर के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई थी।

दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया के नेतृत्व में उस निरीक्षक राकेश सरयाम, बसंत कुमार अह्के, एसएसआई प्रवीण पचौरी सहित कोतवाली पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दिह्ली की घटना के विरोध में बैतूल में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

राहुल गांधी –प्रियंका गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन



परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, रोजगार और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध कर रहे थे। उनके समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग किए

शासकीय कन्या महाविद्यालय में निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस कैम्प का आयोजन

बैतूल। जिला परिवहन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 22 जुलाई को शासकीय कन्या महाविद्यालय में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस कैम्प का आयोजन गया। प्रशासक वन सेंटर महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनामिका तिवारी द्वारा बालिकाओं को कैम्प के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैप केवल लाइसेंस बनवाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार चालक बनने के लिए

प्रेरित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ड्राइविंग लाइसेंस इस बात का प्रमाण है कि चालक यातायात नियमों से परिचित है और सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के योग्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर महिलाओं और युवाओं को बिना लाइसेंस वाहन चलाने के बजाय उचित प्रशिक्षण लेकर वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। कैप के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, हेल्मेट और सीट बेल्ट के महत्व तथा जिम्मेदार ड्राइविंग के बारे में भी जागरूक किया जाता है। सुरक्षित ड्राइविंग केवल हमारी अपनी

सुरक्षा के लिए नहीं, अपितु सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। संचालक महिला एवं बाल विकास विवेक उड्के द्वारा बालिकाओं को विभिन्न विभागीय योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर, साइबर सुरक्षा आदि विषय पर जानकारी दी गई। सीए वन स्टॉप सेंटर श्रीमती शिखा भीरसे द्वारा वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया गया। कैप में जिला परिवहन कार्यालय से अक्षय राने, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.आशीष गुप्ता, 50 से अधिक बालिकाएं, महाविद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे।

नवांकुर अभियान के तहत जिलेभर में दो लाख सीड बॉल से होगा वृद्ध हरियाली महोत्सव : कलेक्टर सोमेश मिश्रा

■ सभी जनपद, तहसीलों और स्थानीय स्तर पर आज आयोजित होंगे कार्यक्रम समितियों के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था में किसानों को खाद उपलब्ध करायें समय अवधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी विकासखंडों में नवांकुर अभियान के अंतर्गत सीड बॉल प्रसार का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वनीकरण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभाग समन्वित प्रयास करते हुए अभियान को सफल बनाएं।

उल्लेखनीय है कि नवांकुर अभियान के तहत जिलेभर में लगभग 2 लाख सीड बॉल का व्यापक स्तर पर प्रसार किया जाएगा। बैठक में खाद एवं उर्वरक वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी समितियों से खाद का नियमित उठाव सुनिश्चित किया जाए।



सहकारिता विभाग साप्ताहिक समीक्षा कर समितिवार डाटा तैयार करे तथा खाद का वितरण रेटेशन के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समिति में खाद की उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जाए। जिन समितियों से खाद का उठाव कम हुआ है, उनकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने के बावजूद उठाव नहीं करने वाली समितियों को नोटिस जारी किए

जाएँ। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने तथा शेष किसानों से भी खाद का उठाव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कृषि एवं संबंधित विभागों को किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा कराने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में शत-प्रतिशत फसल बीमा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विकासखंडों में खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत कम है, वहां संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएं तथा आगामी चार दिवस में शत-प्रतिशत

वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित एसडीएम को जेएसओ के साथ बैठक कर नियमित समीक्षा करने तथा वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में अग्रिम खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मूंग उपाजर्न की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने परिवहन कार्य में तेजी लाने, स्वीकृति पत्रक शीघ्र जारी करने तथा संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर किसानों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉट बुकिंग एवं टोकन जनरेशन में आ रही समस्याओं का संगोष्ठी आयोजित कर त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही

संभागायुक्त कार्यालय के समय-सीमा पत्रों में लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभाग प्रमुखों के एससीएन जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट एवं सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जून माह की रैंकिंग जारी होने के बाद जिन विभागों का प्रदर्शन खराब रहेगा तथा जिन्हें बी, सी अथवा डी श्रेणी प्राप्त होगी, उनके संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेश शुक्ला सहित अन्य जिलाधिकारीगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त दल ने नीमखेड़ा में आंगनवाड़ी केन्द्र का किया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री तथा महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश जैन द्वारा ग्राम नीमखेड़ा में आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले से दस्तक अभियान के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि ग्राम में कोई भी लक्षित बच्चा छूटे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की संख्या तथा उनकी नियमित उपस्थिति, गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण आदि की भी जानकारी ली।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं का किया निराकरण

रायसेन (निप्र)। प्रति मंगलवार की भांति कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनका निराकरण किया गया। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में आए आवेदकों से उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निष्पत्ता से निराकरण किया जाए। जनसुनवाई में लगभग 82 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

लोक सभा सांसद की अनुशंसा पर 03 निर्माण कार्य हेतु 03 लाख 30 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी को अनुशंसा पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा सांक्षर निर्धि से 03 निर्माण कार्य के लिए 03 लाख 30 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सभा सांसद श्री चौधरी की अनुशंसा पर ग्राम व ग्राम पंचायत करनपुर विकासखंड सोहागपुर में श्री रामजानकी मंदिर पूर्व की दिशा में निर्मित शेड के पास सार्वजनिक कवर्ड बैठक स्थल निर्माण कार्य के लिए 02 लाख रूपये, ग्राम खिंडिया ग्राम पंचायत उडियाशंकर विकासखंड सोहागपुर में खेडापति मंदिर के पास सार्वजनिक कवर्ड बैठक स्थल टोन शेड निर्माण के लिए 80 हजार रूपये एवं ग्राम व ग्राम पंचायत परसाई पिपरिया छत्रसाल विकासखंड सोहागपुर में मेन रोड ओनला पिपली के पास सार्वजनिक कवर्ड बैठक स्थल निर्माण के लिए 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीएमएचओ ने किया टीकाकरण शिविरों का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने ग्राम चंदेरी और आलमपुरा में आयोजित टीकाकरण शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने टीकाकरण रजिस्ट्रार के साथ ही वैक्सिन उपलब्धता की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएमएचओ के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारियों ने अलग-अलग केंद्रों पर जाकर शिविरों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है।

मिश्रित दूध का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा खाद्य सुरक्षा विभाग की सतत कार्रवाई जारी



विदिशा (निप्र)।कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं सैपलिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी

क्रम में सोमवार, 20 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सारिका गुप्ता ने दुर्गा नगर, विदिशा स्थित श्री राधेश्याम डेयरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डेयरी से मिश्रित दूध का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत लिया गया। लिया गया

नमूना परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां इसकी गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप होने की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है अथवा अवमानक सिद्ध होता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में मिलावटी एवं अवमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा खाद्य कारोबारियों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। जिला प्रशासन ने खाद्य व्यवसायियों से स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी सभी नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

►► विदिशा में सफलता का गुंजा मंत्रः

किलिमंजारो विजेता पुलिस अधिकारी दीपिका गौतम ने युवाओं को दिया बड़े सपने देखने का संदेश

विदिशा (निप्र)। शासकीय आदर्श महाविद्यालय, विदिशा में ‘प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनें’ विषय पर आयोजित छह दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन प्रेणा, उत्साह और ज्ञानवर्धक संवादों से भरपूर रहा। इस अवसर पर अग्रोका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाली पुलिस अधिकारी दीपिका गौतम ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अपने संघर्ष, अनुशासन और सफलता की प्रेरक यात्रा साझा की। उनके अनुभवों ने विद्यार्थियों में प्रतियोगी परिभाओं और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का नया आत्मविश्वास जगाया। दीपिका गौतम ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परिभाओं की तैयारी के लिए सुनियोजित रणनीति, समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, नोट्स निर्माण और असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

उन्होंने माउंट किलिमंजारो अभियान का अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह केवल शारीरिक क्षमता की नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, धैर्य और संकल्प की भी कठिन परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ ही व्यक्ति

को मजबूत बनाती हैं और कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कार्यक्रम के संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवाओं, यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की तैयारी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अध्ययन तकनीक, नोट्स तैयार करने की विधि तथा करियर निर्माण से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। दीपिका गौतम ने प्रत्येक प्रश्न का सरल, व्यावहारिक और प्रेरणादायी उत्तर देते हुए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एनसीईआरटी पुस्तकों से प्रारंभ करें, प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें, स्वयं के नोट्स तैयार करें, नियमित उत्तर लेखन का अभ्यास करें तथा मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करें। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नियमित दौड़, व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की मेधा शर्मा एवं पप्पी मोना ने भी विद्यार्थियों को भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं में उपलब्ध करियर अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने यूपीएससी, एमपीपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, अध्ययन रणनीति, समय प्रबंधन तथा सफलता के लिए आवश्यक तैयारी पर विस्तार से प्रकाश डाला।

अवैध परिवहन में सिलिप 2 वाहनों को किया जप्त

बैतूल (निप्र)।कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 18 और 19 जुलाई को खनिज विभाग द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ घोड़ाडोंगरी क्षेत्रांतर्गत खनिज मुकम के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0735 को जप्त कर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है एवं बैतूल क्षेत्रांतर्गत ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ के पास से खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन जॉर्नडियर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एच 1136 को जप्त कर पुलिस चौकी खेड़ीसांवलीगढ़ की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।

जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने दिया जा रहा प्रशिक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के मार्गदर्शन में जनगणना-2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ों के संकलन एवं डीसीएचबी पोर्टल के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिले में 17 जुलाई से 28 जुलाई तक पीएम श्री शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण संचालित हो रहा है।

प्रशिक्षण में जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय चार्ज अधिकारियों तथा उनके द्वारा नामित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशाल मध्यप्रदेश भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर श्री भरतलाल गौर एवं सुत्री शालिनी वर्मा द्वारा ग्राम एवं नगर निर्देशिका प्रवेजों के संकलन, आंकड़ों के सत्यापन, डीसीएचबी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के संचालन सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान



जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश भोपाल के संयुक्त निदेशक श्री रामावतार पटेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए जनगणना-2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के महत्व एवं उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला साथ ही जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए आवश्यक आंकड़ों के गुणवत्तापूर्ण, सटीक एवं समयबद्ध संकलन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशिक्षण एक अच्छी पहल होने के सूत्र के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की भूमिका, ग्राम एवं नगर निर्देशिका अनुसूचियों के संकलन, डीसीएचबी

मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के प्रभावी संचालन तथा आंकड़ों के संशोधन एवं सत्यापन की व्यावहारिक प्रक्रिया पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक द्वारा प्रत्यक्ष भेंट कर प्रशिक्षण गुणवत्ता अच्छी होने एवं समय सीमा में होने पर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी श्री भागवानदास कुमरे सहित तहसील भैंसदेही के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

संघर्ष से सम्मान और आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक यात्रा

जल जीवन मिशन ने बदली दित्यांग अभिषेक गुर्जर की जिंदगी

विदिशा (निप्र)। जिले के ग्राम रतवा, ग्राम पंचायत बरुआखर में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का अभियान ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। यह योजना केवल पेयजल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन का आधार भी बन रही है। इसका जीवंत उदाहरण ग्राम रतवा के निवासी श्री अभिषेक गुर्जर हैं, जिनकी जिंदगी इस योजना से पूरी तरह बदल गई है। करीब 1,631 की जनसंख्या वाले ग्राम रतवा में वर्तमान में 181 घरलू नल कनेक्शन क्रियाशील हैं। गांव में वाल्व



ऑपरेटर श्री रकील खान नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार तक प्रच्छ पेयजल पहुंच रहा है। शारीरिक रूप से दिव्यांग श्री अभिषेक गुर्जर के लिए पहले पेयजल की व्यवस्था

परिवार के जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ। अब उनके घर के आंगन में ही नियमित रूप से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री अभिषेक गुर्जर कहते हैं, ‘पहले एक बाटोटी पानी के लिए भी दूसरों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब घर के आंगन में ही नल से पानी मिल जाता है। इस योजना ने हमें आत्मसम्मान और सुविधा दोनों दिए हैं। ‘घर में नल से पानी मिलने के बाद परिवार को रोजाना दूर से पानी ढोने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। अब परिवार के सदस्य अपना समय आजीविका बढ़ाने और बच्चों की शिक्षा पर लगा पा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ



सशक्त वाहिनी एवं नृत्या योजना की 62 बालिकाओं ने किया ग्लोबल स्िकल पार्क का शैक्षणिक भ्रमण

आधुनिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से हुई रूबरू, आत्मनिर्भर बनने की मिली प्रेरणा

विदिशा (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सशक्त वाहिनी कार्यक्रम एवं नव्या योजना के अंतर्गत जिले की 62 बालिकाओं का संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्िकल पार्क (जीएसपी), भोपाल का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य बालिकाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से परिचित कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित करना था। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती विनीता कांसवा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि बदलते समय में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि कौशल आधारित शिक्षा भी सफलता और रोजगार का मजबूत आधार है। भ्रमण के दौरान बालिकाओं ने ग्लोबल स्िकल पार्क में स्थापित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं तथा विभिन्न रोजगारपरक टेब्लों का अवलोकन किया। संस्थान के विशेषज्ञों ने उन्हें उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं, नई तकनीकों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं भविष्य के रोजगार

अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया गया कि तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक कौशल के माध्यम से युवा अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सफल बना सकते हैं। इस अवसर पर ग्लोबल स्िकल पार्क की ओर से सभी बालिकाओं को डायरी एवं संस्थान संबंधी जानकारी से युक्त बोशर भी प्रदान किए गए। आईटीआई विदिशा की प्राचार्या सुश्री कविता रघुवंशी ने बालिकाओं का मार्गदर्शन करते हुए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में कौशल आधारित शिक्षा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। उन्होंने बालिकाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, निरंतर सीखने की आदत विकसित करने तथा आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शैक्षणिक भ्रमण में महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री संतोष रघुवंशी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान बालिकाओं ने विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विशेषज्ञों से करियर, कौशल विकास और रोजगार संबंधी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। भ्रमण के समापन पर बालिकाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से उन्हें आधुनिक तकनीकी शिक्षा, करियर के नए विकल्पों और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई सोच एवं आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। बालिकाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेरणादायी पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

इंदौर में मुख्यमंत्री ने लव-कुश चौराहे का डबल डेकर ब्रिज लोकार्पित किया

ऊपर सड़क , बीच में मेट्रो ट्रैक , सुपर कॉरिडोर की आवाजाही आसान



इंदौर। गुरुवार को इंदौर को विकास की एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लवकुश चौराहे पर प्रदेश के पहले आधुनिक डबल डेकर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस परियोजना के शुरू

होने से शहर की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी, वहीं सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन, सांवेर और सुपर कॉरिडोर की ओर आने-जाने वाले लाखों लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

यह डबल डेकर ब्रिज अपनी आधुनिक संरचना के कारण प्रदेश में विशेष पहचान रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऊपरी स्तर पर सड़क यातायात संचालित होगा, जबकि बीच से मेट्रो रेल का कॉरिडोर

गुजरेगा। इससे सड़क और मेट्रो, दोनों का संचालन एक ही संरचना में संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर आज विकास, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना का प्रतीक बन चुका है। डबल डेकर ब्रिज अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इंदौर को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इंदौर वासियों और प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, बेहतर यातायात और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिज शुरू होने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रा समय बचेगा और आने वाले वर्षों में बढ़ते यातायात को भी सुगमता से संभाला जा सकेगा।

आजाद प्रेरणा मशाल यात्रा का शुभारंभ किया ‘हमेशा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देगा उनका जीवन’



जन्मदिन पर चंद्रशेखर आजाद के गांव पहुंचे सीएम ने किया माल्यार्पण

अलीराजपुर (नप्र)। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम मोहन यादव अलीराजपुर स्थित उनकी जन्मस्थली पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद नगर में सीएम ने उनकी प्रतिमा को नमन किया है और मल्यार्पण किया है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का त्याग, अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श नई पीढ़ी को राष्ट्रसेवा, आत्मसम्मान और देशभक्ति का संदेश देते रहेंगे।

सीएम मोहन यादव ने चंद्रशेखर उद्यान से आजाद प्रेरणा मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, युवाओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा आजाद कुटिया तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आजाद स्मृति मंदिर में प्रदर्शित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन वृत्त का अवलोकन किया। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्म, बाल्यकाल, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा राष्ट्र के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी का अवलोकन किया।

अशोक बर्णवाल ने मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया



भोपाल (नप्र)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (1991 बैच) के वरिष्ठ अधिकारी श्री अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री बर्णवाल को मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव कक्ष में कार्यभार सौंपा। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार 22 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। इससे पहले इसी दिन भारत सरकार द्वारा निवर्तमान मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि उनके विचार देशभक्ति का अमूल्य स्रोत हैं। राष्ट्र के प्रति लोकमान्य तिलक का संघर्ष, नेतृत्व और अद्वितीय योगदान स्मरणीय रहेगा।

हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में विवेक सागर

15 अगस्त से बेल्जियम-नीदरलैंड में होंगे मुकाबले

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी के एसोसिएट खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप-2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम में हुआ है। यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। विवेक एक बार फिर भारतीय टीम की ओर से मिडफील्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे।



अनुभव खिलाड़ियों पर टीम का भरोसा- भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह करेंगे, जबकि मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं। मुख्य कोच क्रेग फ्लूटन ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित संयोजन के साथ विश्व कप में उतरने का फैसला किया है।

19 अगस्त को पाकिस्तान से मुकाबला- भारत को पूल-डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। टीम इंडिया 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान से मुकाबला होगा।

मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात- विवेक सागर प्रसाद लंबे समय से भारतीय टीम के अहम मिडफील्डर रहे हैं। उनका चयन मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी के लिए भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। खेल विभाग का कहना है कि प्रदेश की अकादमियां लगातार ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रही हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

राजस्थान में बांध उड़ाने के लिए चुराई थी शिवपुरी के किले से तोप!

शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन नरवर किले से चोरी हुई ऐतिहासिक तोप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की पड़ताल कर रही शिवपुरी पुलिस को पड़ोसी राज्य राजस्थान के करौली से बेहद अहम इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर चोरों की धरपकड़ के लिए राजस्थान सीमा में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि 15 जुलाई 2026 को नरवर किले से यह बेशकीमती तोप चोरी हुई थी, जिसके बाद से ही स्थानीय इतिहास प्रेमियों में भारी आक्रोश था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है।

तोप से मिट्टी का बांध उड़ाने की साजिश?- इस हाई-प्रोफाइल चोरी में सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आया है। सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के मुताबिक, इस प्राचीन तोप को किसी सामान्य चोरी के इशारे से नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और विशेष



मकसद से चुराया गया था। दावा किया जा रहा है कि चोर इस तोप के जरिए एक बड़े मिट्टी के बांध को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि, प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस बांध उड़ाने की थ्योरी को पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस इनपुट के बाद एमपी और राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

राजस्थान के करौली में एमपी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन- जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी तोप चुराने के तुरंत बाद उसे राजस्थान सीमा में ले गए।

जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे पूर्व कांग्रेस नेता

उल्टा तिरंगा लहरा दिया, मचा बवाल



मंदसौर (नप्र)। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट परिसर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दिक्षी के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे समर्थकों के हाथ में देश का राष्ट्रध्वज 'उल्टा' लगा हुआ दिखाई दिया। इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस से पूर्व में जुड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके स्थानीय नेता श्यामलाल जोकचंद के नेतृत्व में समर्थक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे।

हरा रंग ऊपर, केसरिया नीचे; नारेबाजी में भूल गए तिरंगा

कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल होते समय समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ के बीच चल रहे एक समर्थक के हाथ में जो तिरंगा लहरा रहा था, उसमें हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे की तरफ था। ज्ञापन सौंपने और नारेबाजी करने के दौरान वहां मौजूद किसी भी प्रदर्शनकारी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि राष्ट्रध्वज उल्टा पकड़ा गया है। इसी बीच मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी लापरवाही का अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया।

वीडियो वायरल होने के बाद मची खलबली, प्रशासन अलर्ट

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच राष्ट्रध्वज के अनादर को लेकर तीखी चर्चाएं शुरू हो गईं। वीडियो के वायरल होते ही आयोजकों को भी अपनी इस बड़ी चूक का अहसास हुआ।

डिंडोरी (नप्र)। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें सामने आते रहती हैं। डिंडोरी जिले के एक सरकारी अस्पताल में जहर खाने वाले मरीज को ड्रिप की जगह मिनरल वाटर चढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के सीएमएचओ ने इसमें चूक मानी है।

जिला अस्पताल में है ऐसी व्यवस्था- पूरा मामला डिंडोरी जिला अस्पताल का है। सिविल लाइन निवासी सत्यम कुमार ने किसी वजह से चूहा मारने की दवा खा ली थी। परिजन उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे।

सेलाइन की जगह मिनरल वाटर चढ़ाया- युवक का वहां इलाज शुरू हो गया। लेकिन हद तब हो गई, जब सेलाइन की जगह युवक को मिनरल वाटर चढ़ाया जाने लगा। मिनरल वाटर युवक का पेट साफ



करने के लिए चढ़ाया जा रहा था। अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल

कर दिया।

कार्रवाई के दिए निर्देश- मामला सामने आने के

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी?

राजस्थान पुलिस के सहयोग से सटीक लोकेशन और सदिश्यों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा कर ऐतिहासिक तोप को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।

धरोहरों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

राजा नल और दमयंती की कथाओं से जुड़े नरवर किले का स्थापत्य और इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। किले से भारी-भरकम तोप का चोरी हो जाना और सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसे राजस्थान तक ले जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल पूरी नजर पुलिस के उस खुलासे पर टिकी है जो बांध उड़ाने की इस कथित साजिश का सच सामने लाएगा।

इसके बाद शिवपुरी पुलिस ने करौली पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर संयुक्त रणनीति तैयार की और संदेहस्पद ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों के बेहद करीब पहुंचा जा चुका है।

गुना कलेक्टर पर हाईकोर्ट का हटार

जमीन हड़पने के मामले में रिपोर्ट को बताया ‘मिसलीडिंग’, पेश होने के आदेश

गुना (नप्र)। मध्य प्रदेश के गुना जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के भू-स्वामियों की जमीनों के अवैध कब्जे और शोषण के मामले में हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को ‘पूरी तरह से भ्रामक’ और ‘जवाबदेही से बचने वाली’ करार देते हुए हाईकोर्ट की डिवाइजन बेंच ने गुना कलेक्टर को 28 जुलाई को पूरे ऑरिजिनल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हजर होने का हुक्म सुनाया है।

जरिस्टर जी. एस. अहलूवालिया और जरिस्टस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की रिपोर्ट केवल ‘कागजी खानापूति’ लगती है। इसमें यह पता लगाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई कि एससी/एसटी लाभार्थियों से उनकी जमीन गैर-कानूनी ढंग से छीनी गई है या नहीं।

पावर ऑफ अटॉर्नी और ‘बटाईदारों’ के



खेल पर उठे सवाल- अदालत ने पाया कि सरकार ने गुना जिले के 139 भू-स्वामियों की कृषि भूमि पर ‘बटाईदारों’ (बटाई पर खेती करने वाले) द्वारा खेती किए जाने का दावा तो किया, लेकिन यह जांच ही नहीं की कि वे वैध किसान हैं या दबंगों ने जबरन जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा, गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ के जरिये जमीनों के कब्जे और

ट्रांसफर पर भी कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने कलेक्टर से पूछा कि ऐसे समझौतों को कानूनी कैसे माना जा सकता है, जो आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करते हैं?

हाईकोर्ट के सख्त निर्देश और कलेक्टर से मांगे गए जवाब- बंधुआ मजदूरी पर एफिडेविट-कलेक्टर व्यक्तिगत हलफनामा देकर बताए कि क्या जिले में बंधुआ मजदूरी का कोई मामला पकड़ा गया है और क्या किसी गैर-एससी/एसटी व्यक्ति को आदिवासियों को बंधुआ बनाने के जर्म में जेल भेजा गया है?

बमोरी और आरोन तहसील का रिकॉर्ड: बमोरी और आरोन तहसील में जनजातीय समाज के लोगों को बांटे गए पट्टों और लीज का पूरा ब्योरा पेश किया जाए। **मंडी का डेटा:** कृषि उपज मंडी से 2024, 2025 और 2026 में फसल बेचने वाले आदिवासी किसानों की सही संख्या का डेटा जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

पीडब्ल्यूडी मंत्री की प्राथमिकता में नहीं है यह सड़क

भाजपा के सीनियर विधायक अजय विश्‍नोई ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा

जबलपुर (नप्र)। बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक अजय विश्‍नोई ने अपनी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री को घेरा है। उन्होंने एक्स पर मंत्री के ऊपर निशाना साधा है। अजय विश्‍नोई जबलपुर-पाटन रोड के निर्माण न होने पर नाराज हैं। साथ ही कहा है कि हमने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

रोड निर्माण न होने की वजह से नाराज- विधायक अजय विश्‍नोई ने अपने एक्स पर लिखा कि भोपाल-जबलपुर के पाटन की ओर डायवर्ट किए गए ट्रैफिक ने आज फिर से एक बलि ले ली है। शहपुरा का पुल बन नहीं पा रहा है। सारा हैवी ट्रैफिक पाटन होकर जबलपुर आ रहा है। पाटन की सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी है। हैवी ट्रैफिक ने इस सड़क का सत्यानाश कर दिया है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री की प्राथमिकता नहीं है यह सड़क- बीजेपी विधायक विश्‍नोई ने आगे लिखा कि जबलपुर-पाटन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की योजना को बजट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन यह सड़क पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए इसके निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

सीएम को लिखा पत्र- उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर उन्हें एक पत्र दिया और अनुरोध किया है कि बजट में शामिल पाटन-जबलपुर और पाटन-मानकड़ी सड़क का प्राथमिकता देकर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए।

बाद डिंडोरी सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि मरीज को पेट साफ करने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया गया था। नियमों के अनुसार यह नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी कार्रवाई करेंगे- कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने भी कहा कि जांच के बाद लापरवाहों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आते रही हैं। मरीज खुद ही अपने ड्रिप पकड़े दिख जाते हैं। कहीं मरीजों को एंजुलेंस नहीं मिलता तो कहीं स्ट्रेचर नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी दावों में सब कुछ सही दिखता है।